साप्ताहिक
शहर सत्ता
RNI TITLE CODE - CHHHIN17596
सोमवार, 25 अगस्त से 31 अगस्त 2025
हम दिखाएंगे आईना...
वर्ष : 01 अंक : 25 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 04 में...
गड्ढामुक्त सड़कों के लिए 200 करोड़ में

पेज 12 में...
छग; सेवानिवृत्ति की मेवावृत्ति ...

पेज 07 पुजारा ने लिया संन्यास

आयुष्मान भव: अब नहीं!

भरोसा टूटा, मरीज ईलाज से हो रहे वंचित

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- एक-दो दिन में जारी कर दी जाएगी राशि

भुगतान रुकने से 1 सितम्बर से निजी अस्पतालों में बंद होगी कैशलेस सुविधा

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

रायपुर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना छत्तीसगढ़ में बड़ी चुनौती से गुजर रही है। यहां निजी अस्पतालों के घोषणा ने घोषणा कर दी है कि 1 सितंबर से वे आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज नहीं करेंगे। प्रदेश के निजी अस्पतालों को क्लेम की राशि का भुगतान कई महीनों से नही हुआ है। दूसरी ओर, जांच एजेंसियों ने सरगुजा और अन्य जिलों में फर्जी भर्ती और झूठे इलाज दिखाकर करोड़ों के क्लेम पास कराने का घोटाला उजागर किया है। यानी एक ओर सेवा बंद और दूसरी ओर घोटाला, जिससे आम जनता संकट में है।

अस्पताल मजबूर : 'बिना भुगतान सेवा कैसे दें?'

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) छत्तीसगढ़ ने कहा कि लाखों-करोड़ों रुपये बकाया है। मार्च 2025 में जो आंशिक भुगतान हुआ था, उसके बाद फिर से भुगतान थम गया। डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि सेवाएं चालू रखने के लिए दवाइयां, मशीनें, स्टाफ, सबका खर्च उठाना पड़ता है। जब पैसे ही नहीं मिल रहे तो इलाज मुफ्त कैसे दें? आईएमए के अध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों ने बार-बार सरकार से अपील की, लेकिन स्थिति जस की तस है। अब मजबूरी में 1 सितम्बर से आयुष्मान कार्ड पर इलाज रोकना होगा।

योजना का महत्व और मौजूदा स्थिति

आयुष्मान योजना के तहत गरीबों व कमजोर वर्ग को पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में अब तक लाखों मरीज इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। लेकिन, पिछले दो साल से लगातार अस्पतालों के भुगतान अटकते जा रहे हैं। मार्च 2025 से अब तक कोई नया क्लेम पास नहीं हुआ, जिससे अस्पतालों पर आर्थिक बोझ बढ़ा।

क्या है आयुष्मान भारत योजना?

- केंद्र सरकार की योजना, 2018 में शुरू हुई।
- पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा।
- देशभर के सरकारी व निजी अस्पताल इसमें पंजीकृत।

छत्तीसगढ़ में स्थिति

- लाखों परिवार लाभान्वित
- 300 से अधिक निजी अस्पताल जुड़े
- बकाया भुगतान न मिलने से संकट गहराया

समय पर होगा भुगतान : जायसवाल

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आश्वासन दिया कि जुलाई तक के भुगतान दो से तीन दिनों में कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। एक सितंबर से पहले सारे बकाये चुका दिए जाएंगे। हालांकि अस्पतालों का कहना है कि वादों के बावजूद भुगतान न होना अब आम बात हो गई है।

आईएमए की मांगें

- सभी बकाये का भुगतान ब्याज सहित और एफआईएफओ आधार पर किया जाए।
- योजना का संचालन ट्रस्ट मोड में किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
- शिकायत निवारण समिति बनाई जाए, जिसमें डॉक्टरों और सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।
- आईटी प्लेटफॉर्म पर सभी भुगतान और क्लेम की स्थिति सार्वजनिक की जाए।

जनवरी से मार्च तक 350 करोड़ रुपए की राशि है शेष

निजी अस्पताल एसोसियेशन आयुष्मान योजना की राशि नही मिलने से नाराज होकर स्वास्थ्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए बकाया राशि की मांग की है ताकि वे मरीजों का इलाज बगैर रुकावट कर सकें। एसोसिएशन ऑफ़ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया के प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया से मुलाकात कर वित्तीय भुगतान में आ रही रुकावट से परिचित कराया। स्वास्थ सचिव ने एएचपीआई के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि राज्य शासन ने 31 मार्च 2025 तक का पूरा क्लेम अस्पतालों को दे दिया है और इस संबंध में केंद्र सरकार को ऑडिट रिपोर्ट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी भेज दिया गया है।

इस पर प्रांताध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता एवं अन्य उपस्थित अस्पताल संचालकों ने कहा, जनवरी अंतिम सप्ताह और फरवरी प्रथम सप्ताह के बाद का पूरा क्लेम ज्यादातर अस्पतालों को नहीं मिला है। जनवरी से मार्च 2025 तक का लगभग 350 करोड़ अस्पतालों का बकाया है। अप्रैल से जुलाई तक कुल 700 करोड़ रूपए की राशि अब तक निजी अस्पतालों को नहीं दी जा सकी है।

अप्रूव्ड केस भी रिजेक्ट

वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व हॉस्पिटल बोर्ड की छग और जिला इकाई की संयुक्त बैठक भी इस मामले पर आयोजित की। सदस्यों ने यह जानकारी दी गई कि विगत 6 माह से भुगतान बंद है। मार्च 2025 में सितंबर अक्टूबर 24 का भुगतान आंशिक रूप से दिया गया था। कुछ सदस्यों ने 2023 से भुगतान लंबित होने की सूचना दी है। सदस्यों ने पूर्व में अप्रूव्ड केस को रिजेक्ट किए जाने की सूचना दी है। उनका कहना है कि इससे अस्पतालों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि मरीज इलाज कराकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।

पैकेज दरों की रिवीजन की मांग

डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा, लंबित भुगतान के विषय में यह जानकारी मिलने पर प्रदेशभर के डॉक्टरों में हताशा और रोष है। इस संबंध में शीघ्र ही प्रदेश स्तर के अस्पताल संचालकों से जिला वार विचार विमर्श कर आयुष्मान योजना के लंबित भुगतान, पैकेज दरों के रिवीजन और स्टेट नोडल एजेंसी की संवादहीनता के विषय में आगे की रणनीति तय की जाएगी। हैरानी की बात यह भी है कि आयुष्मान पोर्टल में मार्च के पहले के केस अनपेड दिख रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि इसका पेमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद भी ऑडिट रिपोर्ट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भेज दिया गया है।

सबसे ज्यादा असर गरीब मरीजों पर

राज्य में आयुष्मान कार्ड योजना से अब तक लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। गंभीर बीमारियों और महंगे ऑपरेशन तक कैशलेस सुविधा में शामिल रहे हैं। अब यह सुविधा बंद होने से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को इलाज के लिए जेब से खर्च करना पड़ेगा, कई लोग समय पर इलाज न करा पाने की स्थिति में होंगे साथ ही अचानक निजी सरकारी अस्पतालों में ईलाज न मिलने पर लोग सरकारी अस्पतालों में जाएंगे जिससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ सकता है।

क्या है योजना की पृष्ठभूमि

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलता है। छत्तीसगढ़ में यह योजना लाखों परिवारों तक पहुंच चुकी है और निजी अस्पतालों के सहयोग से गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिली है।

अब आगे क्या?

अब सबकी निगाहें सरकार और आईएमए के बीच होने वाली बैठक पर टिकी हैं। यदि समाधान निकला तो योजना फिर से सुचारु रूप से चल सकती है, लेकिन यदि समझौता नहीं हुआ तो एक सितंबर से प्रदेश में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निजी अस्पतालों का दरवाज़ा बंद हो जाएगा।

आयुष्मान इंटेंसिव: लंबित प्रोत्साहन राशि का 10% तक भुगतान शुरू

आयुष्मान योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने वाले डाक्टरों और चिकित्सकीय स्टाफ के लिए लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान शुरू कर दिया गया है। पिछले दो साल से रुकी राशि का करीब 10 फीसदी अब संबंधित खातों में ट्रांसफर किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, डाक्टरों और अन्य चिकित्सकीय स्टाफ मिलाकर करीब 30 हजार लोगों को कुल लगभग 40 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों के खाते में लंबित राशि सात से दस लाख रुपये तक पहुंच चुकी थी। पांच साल पहले प्रोत्साहन राशि देने का नियम लागू किया गया था ताकि अस्पतालों में टीम भावना और बेहतर उपचार सुनिश्चित हो। नियम के अनुसार अस्पतालों को स्वास्थ्य योजना से मिलने वाली क्लेम राशि का 25 फीसदी हिस्सा चिकित्सकीय स्टाफ को प्रोत्साहन के रूप में देना होता था। सूत्रों के अनुसार, सीनियर डाक्टर और सर्जन लाखों रुपये तक प्रोत्साहन राशि प्राप्त करते थे, लेकिन निचले स्तर के कर्मचारियों को उनका हिस्सा नहीं मिल पाया। इस कारण नाराजगी बढ़ी और वितरण प्रक्रिया पर रोक लग गई। अब भुगतान शुरू होने से कर्मचारियों में राहत की भावना है और अस्पतालों में उपचार व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।

सरकार की लापरवाही के कारण आयुष्मान योजना बंद होने वाली - दीपक बैज

रायपुर। सरकार की लापरवाही के कारण आयुष्मान योजना बंद होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों का भाजपा सरकार भुगतान रोक कर रखी है जिसके कारण निजी अस्पताल वाले आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का इलाज बंद करने की चेतावनी अनेकों बार दे चुके है। पिछले 17 माह से आश्वासन के बाद भी चिकित्सकों का भुगतान नहीं हुआ है। बकाया भुगतान करने की अस्पतालों ने अंतिम चेतावनी भी सरकार को दिया है। उसके बाद भी सरकार अस्पतालों का भुगतान नहीं कर रही है। यदि निजी अस्पतालों ने गरीबों का ईलाज बंद कर दिया तो गरीब वर्ग के लोग मुश्किल में पड़ जायेंगे। अनेक ऐसी बीमारियां है जिनका ईलाज निजी अस्पतालों में ही होता है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में सभी मरीजों का ईलाज हो भी नहीं सकता। अतः सरकार इस मामले में त्वरित निर्णय ले।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर 2018 की तुलना में ढाई गुना बेहतर विकसित किया था। सभी जिला अस्पतालों को मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल के तौर पर विकसित किया था। ब्लॉक के अस्पतालों में भर्ती की सुविधाएं विकसित की थी। अधिकांश जिला अस्पताल में डायलिसिस और क्रिटिकल केयर यूनिट शुरू किए गए थे। 25 लाख तक की मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना छत्तीसगढ़ में संचालित थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में 4000 से अधिक नियमित पदों पर डॉक्टर, नर्स, तकनीशियन और सहायक कर्मचारी की भर्तियां की। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना, हाट बाजार क्लिनिक, मोहल्ला क्लीनिक, दाई दीदी क्लिनिक, हमर अस्पताल और हमर लैब स्थापित किया था लेकिन अब सरकार बदलते ही विगत 11 महीनों के भीतर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा बदहाल हो चुका है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राजधानी के मेकाहारा से लेकर उपस्वास्थ्य केंद्र तक स्वास्थ्य सुविधायें भगवान भरोसे है। भाजपा सरकार की दुर्भावना, उपेक्षा और निकम्मेपन के चलते हैं मामूली बीमारी से बड़ी संख्या में लोग बे-मौत मरने मजबूर हैं। पीलिया, मलेरिया, डायरिया से रोज़ मौत हो रही है।

सुकमा के गोगुंडा गांव में 15 दिनों में 10 आदिवासियों की मलेरिया से मौत हो गयी है। मौसमी बीमारियों से रोकथाम के उपाय बंद होने के कारण विगत 11 महीनों में ही प्रदेश में मलेरिया संक्रमण दर 8 गुना बढ़ गई है। हमर अस्पताल, हाट बाजार क्लीनिक, मोहल्ला क्लीनिक, शहरी स्लम चिकित्सक सेवा कार्यक्रम बाधित है। बड़े ऑपरेशन तो दूर, मामूली इलाज़ के लिए जनता भटक रही है।

स्वस्थ लोगों को भर्ती कर क्लेम, मामला उजागर

सरगुजा जिले में आयुष्मान कार्ड के नाम पर निजी अस्पतालों द्वारा किए जा रहे फर्जी भर्ती व क्लेम का मामला सामने आया है। यहां गोयल हॉस्पिटल में लोगों को कुछ घंटे भर्ती होने पर एक-एक हजार रुपए देकर उनके आयुष्मान कार्ड से बीमा क्लेम किया गया है। जांच में अस्पतालों द्वारा गरीब-मध्यम वर्गीय लोगों और स्वस्थ व्यक्तियों को भर्ती दिखाकर उनके कार्ड से क्लेम पास कराने की बात उजागर हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के जॉइन डायरेक्टर ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। जांच के मुताबिक, कुछ अस्पतालों ने स्वस्थ लोगों को 'बीमार' बताकर भर्ती किया और बिना किसी इलाज के क्लेम बनाया। इन क्लेम में फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल कर लाखों रुपये का फायदा उठा जा रहा था। प्रभावित मरीजों और स्थानीय जांचकर्ताओं ने अस्पताल में भर्ती और इलाज की प्रक्रिया को पूरी तरह अनुचित पाया।

सरकार ने दी सख्त चेतावनी

राज्य सरकार ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों के 28 अस्पतालों का निरीक्षण करवाया और 15 अस्पतालों का आयुष्मान योजना में पंजीयन एक वर्ष के लिए निरस्त कर दिया। अतिरिक्त 4 अस्पतालों को 6 माह के लिए, 4 को 3 माह के लिए निलंबित कर दिया गया, और 5 को चेतावनी पत्र जारी किया गया। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने इस कार्रवाई को आवश्यक बताया, ताकि योजना का लाभ सिर्फ योग्य लोगों तक पहुंचे।

सरकार की नज़र में- क्या भविष्य में बदलाव संभव है?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की एंटी फ्रॉड यूनिट समय-समय पर क्लेम की जांच कर 'ट्रिगर' भेजती है, जिस पर राज्य सरकार स्थानीय निरीक्षण कर कार्रवाई करती रही है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनियमितताओं पर निरंतर निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।

आम जनता पर असर

गरीब और मध्यमवर्गीय मरीजों के लिए योजना के दुरुपयोग से विश्वास हिल रहा है, जो वास्तव में इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड पर निर्भर थे। पारदर्शिता और सत्यापन में कमजोरी उजागर हुई, जिससे योजना की विश्वसनीयता खतरे में है। यदि लोकल अस्पतालों में भी इसी तरह के घोटाले होते हैं, तो मरीजों के लिए सीधे फायदे की बजाय संभावित धोखाधड़ी का डर बन सकता है।

सरगुजा के संदिग्ध अस्पताल

हालांकि वीडियो में अस्पतालों के वास्तविक नाम स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन राज्य में जांच के दौरान कई अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। इनमें रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, रायपुर — कभी निलंबित, बाद में पुनः पंजीकृत। हाई-टेक सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल, भिलाई। स्पर्श मल्टी- स्पेशियालिटी हॉस्पिटल, भिलाई। मार्क हॉस्पिटल, बिलासपुर, ये अस्पताल राज्य में व्यापक गड़बड़ियों के मामले में जांच के दौरान सामने आए थे, जिससे संकेत मिलता है कि सरगुजा क्षेत्र के मामलों में भी इसी तरह की कार्रवाइयां हो सकती हैं।

ड्रग्स सिंडिकेट के 3 और आरोपी गिरफ्तार, कई सफेद पोश भी

दिल्ली से ड्रग्स बेचने आए थे, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

शहर सत्ता/रायपुर। अफगानिस्तान-पाकिस्तान-पंजाब और दिल्ली से ड्रग्स लाकर रायपुर में बेचने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। एक महीने के अंदर पुलिस अधिकारियों ने ड्रग्स बेचने के मामले में 30 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से पुलिस ने करोड़ों का ड्रग्स बरामद किया है। पैडलर्स पर पुलिस के मुखबिर नज़र रखे हुए हैं। शनिवार की शाम पुलिस ने 3 और डीलरों को पकड़ा है। जिनके नाम हर्ष, मोनू और दीप बताए जा रहे हैं। इन आरोपियों के पास से पुलिसकर्मियों ने ड्रग्स बरामद किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। रायपुर पुलिस जल्द पूरे मामले का खुलासा करेगी।

रायपुर पुलिस 2025 से अब तक नशा बेचने वाले 550 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये आरोपी रायपुर में गांजा, एमडीएमए, एलएसडी, ओजी (विदेशी गांजा), हेरोइन, नशे की गोलियां, अफीम, कफ सिरप बेचते और उसे लाते हुए पकड़े गए। इन आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि ये आरोपी ओडिशा से गांजा और महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब-हरियाणा से ड्रग्स लाते और उन्हें रायपुर समेत कई जिलों में बेचते हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में यह आरोपी नशीली सामग्री पहुंचाते हैं। रायपुर के होटलों, पब और फार्म हाउस में आयोजित प्राइवेट पार्टियों में ड्रग्स को कोडवर्ड के सहारे बेचते है।

आरोपियों से गाड़ी भी बरामद

आरोपियों से पूछताछ कर रहे विवेचना अधिकारियों ने बताया कि, आरोपियों के पास से ड्रग्स के अलावा गाड़ी भी बरामद की गई है। आरोपी रायपुर में ड्रग्स कब से बेच रहे थे? ये ड्रग्स कहां का है? किस सिंडिकेट से आरोपी जुड़े हैं? इन सब सवालों का जवाब अफसर तलाश रहे हैं। अफसरों का कहना है कि आरोपियों के सिंडिकेट में कुछ सफेदपोश लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ट्रांजेक्शन सिस्टम, म्यूल एकाउंट्स और कैश फ्लो का ट्रैप

पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन-देन के लिए गिरोह ने म्यूल एकाउंट्स बनाए थे। ऐसे बैंक अकाउंट जिनका उपयोग केवल ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपए के लेन-देन के डिजिटल सबूत मिले हैं। इसके साथ ही क्रिप्टोकरेंसी, UPI और नकद माध्यमों से भी भुगतान होने की भी बात कही जा रही है। इन खातों का संचालन रायपुर से बाहर बैठे सदस्य कर रहे थे, ताकि ट्रैकिंग मुश्किल हो जाए। इससे नशे का कारोबार चलता रहे और आरोपी पकड़े न जाएं।

शराब-घोटाला मामले में 14 दिन की रिमांड पर चैतन्य बघेल

होटल-रियल एस्टेट कारोबारियों को जारी होगा नोटिस

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। चैतन्य को कस्टोडियल रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। चैतन्य बघेल 6 सितंबर तक रायपुर जेल भेज में रहेंगे। इसके पहले ED ने कस्टोडियल रिमांड के दौरान पिछले 5 दिनों तक शराब घोटाला और मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में चैतन्य बघेल से नए तथ्यों पर पूछताछ की है। इसी आधार पर ED कुछ होटल और रियल एस्टेट कारोबारियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। चैतन्य की पत्नी ख्याति वर्मा और उनकी बहनें ईडी कार्यालय पहुंचीं। लगभग आधे घंटे की मुलाकात के बाद वे कार्यालय से बाहर निकलीं और दुर्ग के लिए रवाना हो गईं। चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को भिलाई से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं। ED के मुताबिक शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया। ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फर्जी निवेश दिखाया गया है। साथ ही सिंडिकेट के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग (हेराफेरी) की गई है।

चैतन्य के प्रोजेक्ट में 13-15 करोड़ इन्वेस्ट

ED ने अपनी जांच में पाया कि, चैतन्य बघेल के विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट (बघेल डेवलपर्स) में घोटाले के पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापेमारी कर ED ने रिकॉर्ड जब्त किए थे। प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट राजेन्द्र जैन ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में वास्तविक खर्च 13-15 करोड़ था। जबकि रिकॉर्ड में 7.14 करोड़ ही दिखाया गया। जब्त डिजिटल डिवाइसेस से पता चला कि, बघेल की कंपनी ने एक ठेकेदार को 4.2 करोड़ कैश पेमेंट किया गया।

रायपुर में काली कमाई के लिए बैंक अकाउंट खुलवाए

3 बैंक के अधिकारी गिरफ्तार, पैसों के बदले ब्रोकरों की मदद की थी

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर में फ्रॉड के पैसे बैंक खातों में मंगवाने के लिए बैंक अकाउंट खोले गए। इस मामले में पुलिस ने तीन अलग-अलग बैंक के अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। जिन्होंने ब्रोकरों से पैसे लेकर उनकी मदद की। इन्हीं म्यूल बैंक अकाउंट से ठगो ने लाखों रुपए ट्रांसफर कर वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस के मुताबिक, रायपुर के टिकरापारा, सिविल लाइन और गुढ़ियारी थाने में ठगी की अलग-अलग शिकायत दर्ज की गई। जिसके बाद म्यूल बैंक खाता का संचालन करने वाले और खुलवाने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है। इस मामले में पुलिस ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत की भी जांच की। जिसके बाद एक्सिस बैंक अधिकारी अभिनव सिंह, इंडियन ओवरसीज बैंक अधिकारी प्रवीण वर्मा, रत्नाकर बैंक अधिकारी प्रीतेश शुक्ला की गलत तरीके से बैंक अकाउंट खुलवाना मिला। आरोपियों ने बैंक के ड्यू डीलीजेन्स, के वाई सी नॉर्म्स का पालन नहीं किया था। इसके अलावा बैंक खाता खोलने के बदले ब्रोकरों से रुपए लिए थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

गिरफ्तार बैंक अधिकारी

- अभिनव सिहं पिता नरेश सिंह (32) झण्डा चौक सेक्टर 02 शिवानंद नगर खमतराई रायपुर (एक्सिस बैंक)
- प्रवीण वर्मा पिता लक्ष्मण प्रसाद वर्मा (37) पता रोहिणीपुरम फेस 1 बोरसी, पदमनाभपुर, दुर्ग (इंडियन ओवरसीज बैंक)
- प्रीतेश शुक्ला पिता लालजी शुक्ला (32) पता शिवानंद नगर, गुढियारी रायपुर (रत्नाकर बैंक लिमिटेड)

बाइक खड़ी ट्रक से टकराई 2 दोस्तों की मौत

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर के गोबरा नवापारा में एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दोनों दोस्त अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान रात के अंधेरे में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पिछले हिस्से से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रायपुर जिले के गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार, नवागांव के निवासी डेमन साहू (40 वर्ष) और जितेंद्र ध्रुव (40 वर्ष) दोनों दोस्त हैं। दोनों के घर आसपास में हैं। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त शनिवार को किसी काम से दूसरे गांव गए थे। रात में वे घर लौट रहे थे। इसी दौरान नवागांव-रायपुर रोड पर नवागांव से 1 किमी दूर रात करीब 9.15 बजे यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक लोहे की छड़ों से भरा हुआ था। ट्रक अंधेरे में सड़क किनारे खड़ा था। ड्राइवर ने किसी प्रकार का संकेतक भी नहीं लगाया था। दोनों युवकों की बाइक तेज रफ्तार होने के कारण ट्रक नहीं दिख पाया। वे ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गए।

महादेव सट्टा ऐप : सौरभ-रवि ने कोर्ट से मांगी 3 महीने की मोहलत

कहा-गैर जमानती वारंट निरस्त कीजिए, कोर्ट में खुद हाजिर होंगे

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव सट्टा ऐप के प्रमुख संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में याचिका लगाई है। गैर-जमानती वारंट (NBW) रद्द करने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला 3 नवंबर तक सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सौरभ और रवि के वकील ने कोर्ट से 3 महीने की मोहलत देने की मांग की है। आरोपियों के वकील ने कहा है कि दोनों खुद कोर्ट में पेश (सरेंडर) होंगे। आप वारंट कैंसिल कर दीजिए। हमें समय दे दीजिए, वह कोर्ट में पेश हो जाएंगे। दरअसल, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लोकसभा में बिल पारित होने और ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के कानून के बाद गैरकानूनी ऑनलाइन गैंबलिंग चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने याचिका लगाई है।

हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी है याचिका

ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ED के समन के बावजूद पूछताछ में हाजिर नहीं हो रहे थे। इसके बाद स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। दोनों ने हाईकोर्ट में गैर-जमानती वारंट रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली और उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। रवि उप्पल ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जो अभी पेंडिंग है। रायपुर के स्पेशल कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से नया आवेदन पेश किया गया है। कोर्ट ने अपना फैसला 3 नवंबर तक सुरक्षित रख लिया है।

स्पेशल कोर्ट में सुनवाई में यह हुआ

शनिवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के वकील ने गैर-जमानती वारंट रद्द करने की मांग की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि आप वारंट कैंसिल कर दीजिए। हमें 3 महीने का समय दे दीजिए हम कोर्ट में पेश हो जाएंगे।

शर्त और सशर्त में अटका मामला

सौरभ पांडे ने बताया कि कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की ओर से तीन महीने का समय देने की मांग की गई। वहीं ईडी की तरफ से आज फिर से कहा गया कि अगर आरोपी बिना किसी शर्त (अनकंडीशनल) पेश होने का प्रस्ताव देते हैं, तभी वारंट कैंसिल करने पर विचार किया जा सकता है। ED के वकील ने बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में ईडी की ओर से बिना किसी शर्त के पेश होने का एक प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उस समय आरोपियों के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि ईडी उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछा रही है। इसी वजह से उन्होंने ईडी के अनकंडीशनल ऑफर को ठुकरा दिया था।

प्रदेशभर की सड़कों को गड्ढामुक्त करने 200 करोड़ रुपए की मंज़ूरी

विभाग ने प्रदेशभर से मंगाई है खराब सड़कों की जानकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सभी खराब सड़कों व पुल-पुलियों को गड्ढामुक्त, मरम्मत, पॅचवर्क व डामरीकरण करने का काम जल्द शुरू यह किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने मरम्मत व पेंचवर्क योग्य सड़कों का चिन्हांकन कर कार्ययोजना तैयार ली है। राज्य शासन ने इन सड़कों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दे दी है। वहीं, विभागीय अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर जारी करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

बारिश सीजन के तुरंत बाद सितंबर माह में सड़कों के पेंचवर्क का काम शुरू हो जाएगा। अधिकारियों का दावा है कि सभी खराब सड़कों को 31 दिसंबर तक गड्ढा मुक्त कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री अरुण साव हाल ही में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में सड़कों व पुल-पुलियों पुल-पुलियों की क खराब स्थिति को लेकर गहरी नाराजगी जता चुके हैं और अधिकारियों को प्रदेश की सभी सड़कों को 31 दिसंबर तक गड्ढा मुक्त करने कहा है। उप मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने सभी जिलों से तत्काल मरम्मत की जरूरत वाली सभी खराब सड़कों व पुल पुलियों की विस्तृत रिपोर्ट मंगाई। एक-एक किमी सड़क की स्थिति का पूरा लेखा जोखा विभाग के पास पहुंच चुका है। लोक निर्माण विभाग को राज्य की ऐसी सभी सड़कें जिनकी मरम्मत की जरूरत है, को सर्वोच्च प्राथमिकता से कराए जाने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य की सभी खराब सड़कों की मरम्मत, पेंचवर्क व डामरीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बरसात के चलते कार्य मरम्मत कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है। लोक निर्माण विभाग अब जल्द ही सड़कों की मरम्मत का काम शुरू करेगा, ताकि सड़क आवागमन सुविधाजनक हो सके।

बताया गया है कि प्रदेशभर में ज्यादातर सड़कों की हालत खराब है। राज्य व जिला मार्गों के अलावा ग्रामीण सड़कों की स्थिति भी बेहद जर्जर है। जगह-जगह गड्ढे हैं। बरसात के दिनों में इन सड़कों पर राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है। वहीं, सड़क दुर्घटनाएं होने का खतरा भी है। इसके चलते आम जनता में सरकार के प्रति आक्रोश भी है। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कार्ययोजना बनाई है।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में बारिश खत्म होते ही सितंबर माह से सड़कों व पुल-पुलियों के मरम्मत कार्य में तेजी आएगी। आबंटित राशि का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाएगा। सड़क व पुल-पुलियों की मरम्मत सहित अन्य संधारण कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पेंच रिपेयर के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रमुख अभियंता ने सभी विभागीय अधिकारियों को टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। सितंबर से बीटी पेच रिपेयर कार्य अनिवार्य रूप से चालू कर दिया जाएगा। पेंच रिपेयर कार्य आईआरसी मानकों के अनुसार कराएंगे।

मरम्मत कार्यों की होगी निगरानी

अनुबंध के मुताबिक खराब मार्गों के रिपेयर कार्यों की समीक्षा होगी। प्रत्येक सप्ताह अधीक्षण अभियंता व प्रतिमाह मुख्य अभियंता मौके पर जाकर समीक्षा कर प्रतिवेदन प्रमुख अभियंता को देंगे। पेच रिपेयर कार्यों में आयटममेजरमेंट के भौतिक सत्यापन के लिए डिजिटल फोटोग्राफी के साथ ही कार्यपालन अभियंता भी सत्यापन करेंगे।

कोरबा में बंद पड़े आधे से अधिक जनधन खाते

कोरबा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में से कोरबा जिले के लगभग 50 फीसदी खाते निष्क्रिय हो चुके हैं। ऐसे खातों की संख्या करीब चार लाख बताई जा रही है। वित्त मंत्रालय ने इस पर गंभीरता जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी बंद खातों को जल्द से जल्द चालू किया जाए।

RBI अधिकारी ने जताई चिंता

हाल ही में आरबीआई, रायपुर के महाप्रबंधक कोरबा प्रवास पर पहुंचे। यहां बैंक की ओर से आयोजित एक शिविर में उन्होंने मौके पर ही 50-60 खातों को पुनः सक्रिय कराया और बड़ी संख्या में बंद पड़े खातों को लेकर चिंता जाहिर की। इसके बाद जिले के सभी बैंकों को निष्क्रिय खातों की लिस्टिंग कर पुनः सक्रिय करने के लिए कहा गया है।

KYC नहीं होने से बंद हुए खाते

बैंकों के अनुसार, खाते निष्क्रिय होने की मुख्य वजह है कि नियमित KYC अपडेट नहीं कराया गया। बैंकिंग नियमों के तहत हर खाते की 10 साल में कम से कम एक बार KYC आवश्यक होती है। चूंकि 2014 में जनधन योजना की शुरुआत के बाद अब 10 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए बड़ी संख्या में खातों को ब्लॉक कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी और एक परिवार में एक से अधिक खाते खुलवाने जैसी वजहों से भी यह समस्या बढ़ी है।

ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का गृह मंत्री शाह ने किया शुभारंभ

रायपुर। प्रथम निर्वाचित भारतीय स्पीकर श्री वीर विट्ठल भाई पटेल जी के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर दिल्ली विधानसभा में आयोजित दो दिवसीय ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ आज देश के केंद्रीय गृह मंत्री मान.श्री अमित शाह जी ने किया।

इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह जी सहित देश के अन्य विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। यह दो दिवसीय सम्मेलन 24 और 25 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर विधानसभा सचिव श्री दिनेश शर्मा भी उपस्थित थे।

अतिथि व्याख्याता भर्ती विवाद

दूसरे प्रदेश के युवाओं की नियुक्ति पर बवाल, जांच समिति गठित

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में दूसरे प्रदेश के युवाओं को अतिथि व्याख्याता नियुक्त करने को लेकर विवाद बढ़ गया है। स्थानीय युवाओं में नाराजगी फैलने के बाद छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता संघ ने कॉलेज प्राचार्यों पर मनमानी नियुक्ति देने का आरोप लगाया और उच्च शिक्षा मंत्री से शिकायत की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात कर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने और जाँच कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद विभाग ने संभागवार जाँच समिति गठित की और जाँच रिपोर्ट 7 दिनों में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। वहीं, जिन कॉलेजों में नियुक्ति हो चुकी है, वहां नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। संघ के अध्यक्ष लव वर्मा ने कहा कि जाँच समिति में प्राचार्यों को शामिल करना समझ से परे है, क्योंकि प्राचार्यों की मनमानी के कारण ही स्थानीय युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि कई कॉलेजों में नियुक्तियाँ पहले ही दूसरे प्रदेश के युवाओं को दे दी गई हैं और इसे स्थगित किया जाना चाहिए।

वंदे भारत कोच की धुलाई के दौरान हाई वोल्टेज हादसा, युवक झुलसा

बिलासपुर। रेलवे कोचिंग डिपो में वंदे भारत के एक्स्ट्रा कोच की सफाई के दौरान शनिवार को गंभीर हादसा हो गया। एक ठेका कर्मचारी प्रताप बर्मन (जांजगीर-चांपा निवासी) 133KV हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। घटना के दौरान प्रताप कोच की सफाई कर रहा था, तभी अचानक लाइन चालू कर दी गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक झुलसने के बाद दर्द से तड़प रहा था। साथी कर्मचारियों का कहना है कि रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। प्रताप को पहले रेलवे अस्पताल लाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सिम्स रेफर किया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि हादसे के बाद घायल कर्मचारी के इलाज पर ध्यान दिया जा रहा है और घटना की जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री साय के नेवता पर उमड़ा महिला शक्ति का सैलाब, डिप्टी सीएम साव बोले– नारी गौरव को मिल रहा बढ़ावा

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव : महिला सम्मेलन और तीजा-पोरा की धूम

रायपुर। राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार तीजा-पोरा धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेवता पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में प्रदेशभर से आईं हजारों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भव्य आयोजन में महिलाओं का आत्मीय स्वागत किया गया और उन्हें उपहार स्वरूप साड़ी, श्रृंगार सामग्री और छत्तीसगढ़ी कलेवा भेंट किया गया। मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने तीजा पर्व की शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह पर्व छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति के मान, सम्मान और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ महतारी के गौरव को बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। डिप्टी सीएम साव ने महतारी वंदन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की 70 लाख से अधिक माताओं-बहनों को हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे परिवार के साथ समाज में भी सशक्त भूमिका निभा रही हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, पूर्व सांसद सरोज पांडेय, रायपुर की महापौर मीनल चौबे सहित कई गणमान्यजन उपस्थित रहे।

सांस्कृतिक रंग और पारंपरिक आभा

महिला सम्मेलन के दौरान ऑडिटोरियम छत्तीसगढ़ी परंपरा से सजा नजर आया। महिलाओं ने मेहंदी, आलता, चूड़ियों से सजधज कर झूले का आनंद लिया। पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले और लोकगायिका आरु साहू की प्रस्तुतियों ने माहौल को छत्तीसगढ़ी रंग में रंग दिया। सम्मेलन में पारंपरिक आभूषणों और कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें तोड़ा, पैरी पैजन, लच्छा, सांटी, झांझ, बिछिया सहित अनेक लोक आभूषण और वाद्ययंत्र आकर्षण का केंद्र बने।

प्रतियोगिताओं में उत्साह

महिला सम्मेलन में कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़, नींबू दौड़ और रस्साकशी जैसी प्रतियोगिताओं में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे सभागार में तालियों और हंसी की गूंज ने उत्सव को जीवंत कर दिया।

संपादकीय

• सुकांत राजपूत

राजनीतिक अभियांत्रिकी

छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार पर भाजपा का प्रदेश संगठन खुद क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक असंतुलन की बहस में व्यस्त है। पार्टी संगठन का एक धड़ा इसे राजनीतिक अभियांत्रिकी की धज्जियां उड़ने वाला बता रहा है। स्वाभिक भी है नाराज़ धड़ा यह बोलकर विधानसभा सत्र में दुश्मनी भंजाने की ठान लिया है। वैसे भी अब तक सत्ता पक्ष पर सदन में विपक्ष से ज्यादा मुखर और आक्रामक तो भाजपा के वरिष्ठ विधायक दिखे। वरिष्ठ भाजपाई शुरू से भनभनाते रहे हैं कि कांग्रेस से आए नेताओं को पार्टी दोनों हाथों से उपकृत कर रही है।

बीजेपी ने तीन नए मंत्री बना दिए मगर विभाग बांटने के मामले में फुटकर बनियों जैसे डंडी मार दी। गजेंद्र यादव को तो स्कूल शिक्षा कुछ ठीक भी है, बाकी दो की स्थिति ऐसी रही कि मंत्री बनने की खुशी मनाएं या फिर मलाईदार विभाग न मिलने का गम। तीन में से एक मंत्री इस प्रोफाइल के हैं कि उन्हें जो मिला है, उसके बजट से कई गुना ज्यादा उनका खुद का जमा-जुमाया धंधा है।

बीजेपी यूं तो राजनीतिक और पार्टीगत अभियांत्रिकी में करीब करीब कामयाब हो गई मगर पार्टी के भीतर ही इस पर असंतोष है कि क्षेत्रवार संतुलन बनाने का प्रयास नहीं किया गया। पहली बात यह कि बस्तर से एक की तुलना में मंत्रिपरिषद में सरगुजा से पांच-पांच लोग हो गए हैं। अंबिकापुर से अखिलेश सोनी को बीजेपी कार्यकारिणी में महामंत्री बनाया गया, और वहीं से राजेश अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री भी। इसी तरह आरंग से नवीन मार्केडेय को महामंत्री और वहीं से खुशवंत साहेब को सरकार के मंत्री। जांजगीर में पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया, मगर वहां से किसी को कार्यकारिणी में पदाधिकारी बनाने की जरूरत नहीं समझी गई। बिलासपुर जैसे सूबे के दूसरे बड़े जिले से न तो किसी को कार्यकारिणी में पद मिला और न मंत्रिमंडल में। बहरहाल, गजेंद्र यादव के नाम पर काफी पहले से सहमति बन गई थी, मगर खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल को लेकर बीजेपी में पर्दे के पीछे शह-मात का खेल चला, उससे पार्टी के दिग्गज नेता भी भौंचक हैं। अब देखना है कि बीजेपी के रणनीतिकार इस असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं।

आवारा कुत्तों के मामले में कई पहलू समझें

विराग गुप्ता

मुम्बई में कबूतरों को दाना देने पर एफआईआर और दिल्ली में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सार्वजनिक विमर्श में ध्रुवीकरण हो गया है। लेकिन इस फेर में हमें बहस के छह वास्तविक और बड़े बिंदुओं को नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहिए।

1. कानून

नसबंदी और रैबीज इंजेक्शन के बाद उसी स्थान पर कुत्तों को छोड़ने के नियम को सुप्रीम कोर्ट के जज ने बेतुका बताया है। कई लोग मनुष्यों की तरह कुत्तों के लिए भी जीवन की सुरक्षा और घूमने-फिरने के संवैधानिक अधिकार को मानते हैं। लेकिन फिर उस तर्क के अनुसार बकरी, भैंस, मुर्गा आदि के जीवन के अधिकार का सम्मान करते हुए देश में तमाम प्रकार की पशु-क्रूरताओं पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। विशेष दर्जा देने के तर्क के साथ कानून के अनुसार जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी। कोई इंसान अगर दुर्व्यवहार या हिंसा करे तो उसे जेल भेजा जा सकता है। इसी तरह से हमला करने और काटने वाले कुत्तों को भी आबादी से दूर भेजना न्यायसंगत है।

2. स्वच्छता

राजधानी दिल्ली में सिर्फ 5767 कुत्तों का एमसीडी में रजिस्ट्रेशन कराया गया है। डेंगू और मलेरिया रोकने के लिए भी कूलर के पानी की जांच होती है। इसी तरह सड़क, पार्क और कॉलोनियों में करोड़ों कुत्तों के शौच, पेशाब, जूठन खाने आदि की वजह से बढ़ रही गंदगी और बीमारियों को रोकने के लिए भी नियमों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। कोरोना के वायरस को रोकने के लिए पूरे देश की जनता को क्वारेंटाइन और लॉकडाउन में झोंक दिया गया था। इसी आधार पर हिंसक या खतरनाक कुत्तों को भी आबादी से दूर भेजने की जरूरत है।

3. जज

4 साल पहले केरल हाईकोर्ट ने ब्रूनो कुत्ते की हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। इसलिए करोड़ों लोगों की सुरक्षा से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई अब तीन जजों की नई बेंच करेगी। पिछले कई फैसलों पर हो रहे विवादों से साफ है कि जजों की व्यक्तिगत अभिरुचि और मीडिया के दबाव के बगैर संविधान और कानून के अनुसार अदालत के फैसले होने चाहिए। आनन-फानन में जज बदलने या फैसलों को पलटने से जजों के साथ सर्वोच्च न्यायालय का मान कमजोर होता है। पटाखे और वाहनों पर प्रतिबंध के पुराने फैसलों पर विवाद से साफ है कि जनहित से जुड़े मामलों में राजधानी दिल्ली या एनसीआर की बजाय पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू होने चाहिए।

4. रैबीज

पिछले साल भारत में लगभग 6 करोड़ आवारा कुत्तों के काटने के 37 लाख से ज्यादा मामले आए। जबकि सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में 11 लाख आवारा कुत्तों ने इस साल अभी तक लगभग 6.62 लाख लोगों को काट लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार रैबीज की वजह से साल 2004 में भारत में 20,565 सालाना मौतें हुई थीं, जो कि पूरी दुनिया में रैबीज से होने वाली मृत्युओं का 35 फीसदी है। रैबीज केवल कुत्तों से ही नहीं फैलता, लेकिन इसके 96 फीसदी से ज्यादा मामले कुत्तों के काटने से ही होते हैं। चिंताजनक बात यह है कि एंटी रैबीज वैक्सीन के साथ ही इम्युनोग्लोबुलिन भी दिया जाता है, जो देश के अधिकांश अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है।

5. मुआवजा

सर्पदंश के सालाना 58 हजार मामलों की अब बीमारी के तौर पर रिपोर्टिंग जरूरी हो रही है। उसी तर्ज पर कुत्तों के काटने के हर मामले की रिपोर्टिंग भी जरूरी है। एक स्ट्रीट डॉग को लाठी से पीटने के मामले में दिल्ली पुलिस के एएसआई के खिलाफ साढ़े तीन साल बाद मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी तर्ज पर कुत्तों के काटने के मामले में मालिकों और अनुचित संरक्षण देने वालों पर मुकदमा होना चाहिए। आक्रामक कुत्तों की ब्रीडिंग और उनको पालने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कुत्तों के काटने के सभी मामलों में फ्री इलाज के साथ पीड़ित व्यक्ति और परिवार को समुचित मुआवजा मिलना चाहिए।

6. बजट

आवारा कुत्तों के बढ़ते संकट में नसबंदी, रैबीज इंजेक्शन और शेल्टर हाउस हजारों करोड़ के फंड में एनजीओ और अफसरों का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। देश में 40% आबादी पोषक भोजन से वंचित है तो फिर दिल्ली के कुत्तों के विस्थापन के लिए 15 हजार करोड़ रुपए के खर्च का जुगाड़ कैसे होगा? आज भारतीय पेट-केयर का बाजार ही एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। समृद्ध वर्ग के पशु प्रेमियों को आयातित कुत्तों के बजाय आवारा कुत्तों को गोद लेने के साथ उनके कल्याण की योजनाओं को सफल बनाने के लिए सीएसआर की तर्ज पर अधिकतम आर्थिक सहयोग देना चाहिए।

दिल्ली-एनसीआर में 11 लाख कुत्तों ने इस साल अभी तक लगभग 6.62 लाख लोगों को काट लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार रैबीज से 2004 में भारत में 20,565 सालाना मौतें हुई थीं, जो पूरी दुनिया की 35% थीं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सुशील भोले

कोंदा-भैरा के गोठ

-गरियाबंद के सरकारी अस्पताल म मरीज मन के जान ल अब महिला सुरक्षा गार्ड के भरोसा छोड़ दिए गे हवय जी भैरा.

-कइसे उजबक बानी के गोठियाथस जी कोंदा.. डॉक्टर अउ नर्स मन कहाँ चल दे हें तेमा सुरक्षा गार्ड के भरोसा मरीज मन ल छोड़हीं?

-कोन जनी संगी.. फेर अभी एक विडीयो वायरल होवत हे, जेमा महिला सुरक्षा गार्ड ह एक झन मरीज ल इंजेक्शन लगावत हे.

-करलई हे संगी.. सरकारी अस्पताल मन के संबंध म एक ले बढ़ के एक किस्सा सुने बर मिलथे, तेमा के इहू ह एक ठ अनभरोसिल बरोबर जनाथे.

-हव.. अनभरोसिल तो जनाथे फेर ए ह सोला आना सच आय.

-अइसने सब नजारा मनला देख के लोगन सरकारी ठीहा म जाय बर थथमराए असन करथें, फेर काय करबे गरीब-गुरबा मन जगा अउ कोनो विकल्प घलो तो नइ राहय.. निजी अस्पताल म जाबे त उहाँ के डॉक्टर मन डकैत बरोबर जनाथें.. जेन रोग के इलाज ह सौ दू सौ रुपिया म हो सकथे, तेकर बर उहाँ बीस-तीस हजार के बिल बन जाथे.

-सही आय जी.. अइसन म कमजोरहा लोगन का करय.. सरकारी अस्पताल ल ही अपन जिनगी के लेखा-सरेखा ल सउँप देथें.

पोरा या पोला?

सुशील भोले

आदि धर्म जागृति संस्थान, रायपुर

आजकाल ए देखे म जादा आवत हे, के हमर इहाँ के लोगन अपन परंपरा-संस्कृति के मूल स्वरूप ल जाने-समझे ल छोड़ के पर के पाछू भेड़िया धसान बरोबर किंजरई ल जादा गरब के मान डरथें. अभी बीते दिन कमरछठ परब ल देखे रेहेन, लोगन उत्तर भारत ले आए लोगन मन के देखासिखी एला हलषष्ठी बतावत बलराम जयंती काहत रिहिन हें. एदे अब अवइया 'पोरा' परब के संबंध म घलो अइसने देखे जावत हे. पोरा ल हिंदीकरण करत 'पोला' कहे जावत हे, सोशलमीडिया के ठीहा तो अंखमूंदा मन के बसेरा बनगे हवय.

असल म हमर छत्तीसगढ़ म मनाए जाने वाला परब ह 'पोरा' आय. छत्तीसगढ़ी भाखा म पोला शब्द छेदा, भोंगरा या पोलपोला खातिर उपयोग करे जाथे. जबकि हमर इहाँ पोरा के परब मनाए जाथे, वो ह धान म पोर फूटना, पोटरी या पोठरी पान धरे के अवस्था, जेला गर्भधारण के अवस्था कहे जाथे, तेकर सेती मनाए जाथे. एकरे सेती ए दिन किसान मन अपन अपन खेत म पोरा म रोटी पीठा भर के चढ़ाथें, जे ह धान के फसल ल गर्भधारण करे के सेती सधौरी खवाए के प्रतीक स्वरूप होथे. जइसे हम अपन बेटी-माई मनला पहिली बेर गर्भधारण करे म सधौरी खवाथन.

पोरा के दिन माटी के बने नँदिया बइला के पूजा घलो करथन, अउ फेर पूजा के पाछू लइका मन नँदिया बइला म डोरी बॉंध के नँगत किंजारत खेलत रहिथें. ए दिन नँदिया बइला ल जेन ठेठरी अउ खुरमी चढ़ाए जाथे, वोला पहिली विशेष रूप ले बनाए जावय. ठेठरी ल जलहरी के रूप म अउ खुरमी ल शिवलिंग के रूप म नँदिया बइला के पूजा के बेरा जब दूनों ल समर्पित करे जावय त ठेठरी के ऊपर म खुरमी ल मढ़ाए जावय, एकर ले दूनों मिल के एक पूर्ण शिवलिंग बन जावय.

पोरा के दिन पहिली गोल्लर ढीले के परंपरा घलो रिहिसे. जेन कोनो मनखे ह मनौती माने राहय या शिव सवारी नंदी खातिर कोनो किसम के श्रद्धा राखय, वो ह पोरा के दिन गोल्लर के पीठ म या वोकर जाँघ म भोलेनाथ के त्रिशूल के चिनहा आँक के गोल्लर के पूजा पाठ कर के ढील देवय. ए ढीले गे गोल्लर ल पूरा गाँव वाले मन देवता बरोबर मानँय.

असल म पोरा परब के दिन ही नंदीश्वर जन्मोत्सव होथे, तेकरे सेती ए सब करे जावय. आज हम अपन संस्कृति के आध्यात्मिक स्वरूप ल चुकता भुलागे हावन, तेकर सेती एला सिरिफ कृषि संस्कृति के रूप भर म सुरता करथन, जबकि हमर हर परब संस्कृति के संबंध कोनो न कोनो रूप ले अध्यात्म संग घलो हे.

अब बतावौ संगी हो ए परब ह असल म 'पोरा' आय या पोला?

बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे : राहुल गांधी

बिहार के अररिया में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देशभर में वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे हुए है. वहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग अब "गोदी आयोग" बन गया है और बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है.

वोट चोरी हो रही है

राहुल गांधी ने कहा कि अब करोड़ों लोग मानते हैं कि वोट चोरी हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में उनकी पार्टी को वोटर लिस्ट तक नहीं दी गई. राहुल ने कहा- "हमने कर्नाटक में दिखाया कि कैसे वोट की चोरी हुई. बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे." उन्होंने यह भी बताया कि उनकी यात्रा के दौरान छोटे-छोटे बच्चे आकर कह रहे हैं - "वोट चोर गद्दी छोड़." राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग अगर इन बच्चों से बात कर ले, तो सच्चाई खुद पता चल जाएगी.

चुनाव आयोग से किए सवाल

राहुल गांधी ने कहा- "मैंने कर्नाटक के महादेवापुरा से जुड़ा डेटा रखा और चुनाव आयोग से पूछा कि 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए? चुनाव आयोग का जवाब अभी तक नहीं आया. मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही चुनाव आयोग ने मुझसे एफिडेविट मांगा. कुछ दिन बाद BJP के अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन चुनाव आयोग ने उनसे एफिडेविट नहीं मांगा. मैंने फर्जी वोटर की बात की, अनुराग ठाकुर ने भी वही बात दोहराई, लेकिन चुनाव आयोग का उनसे एफिडेविट न मांगना दिखाता है कि चुनाव आयोग न्यूट्रल नहीं है. SIR संस्थागत वोट चोरी करने का तरीका है. बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, लेकिन BJP एक शिकायत नहीं कर रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त और BJP के बीच पार्टनरशिप है."

तेजस्वी यादव का हमला - "चुनाव आयोग बना बीजेपी का कार्यकर्ता"

तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा - "अब चुनाव आयोग गोदी आयोग हो गया है. वह बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है. ज़मीनी स्तर पर हम घूमे हैं और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो गई है." तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा - "इतना झूठा पीएम हमने आज तक नहीं देखा. अफवाह फैलाना इनका काम है. जब बिहार आए तो घुसपैठियों का जिक्र किया, लेकिन चुनाव आयोग के एफिडेविट में एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं है।"

क्या बांग्लादेश से माफी मांगेगा पाकिस्तान?

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार तीन दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश पहुंचे हैं. पाकिस्तान ने इस दौरे को "ऐतिहासिक" बताया है क्योंकि एक दशक से भी ज्यादा समय बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री बांग्लादेश गया है. इससे पहले हिना रब्बानी खार ने 2012 में ढाका की यात्रा की थी. इस दौरे को लेकर चर्चा है कि क्या पाकिस्तान 1971 के मुक्ति संग्राम में अपनी भूमिका के लिए माफी मांगेगा. इशाक डार अप्रैल में ढाका जाने वाले थे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारतपाकिस्तान तनाव बढ़ने से दौरा टाल दिया गया था. अब शनिवार (23 अगस्त,2025) दोपहर वे ढाका पहुंचे, जहां उनका कई राजनीतिक दलों से स्वागत हुआ. ढाका पहुंचने के बाद डार ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP), जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश और नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) के नेताओं से मुलाकात की. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि डार ने एनसीपी नेताओं की "सुधारवादी सोच और सामाजिक न्याय के विजन" की सराहना की और युवाओं के बीच ज्यादा संवाद पर जोर दिया।

गगनयान मिशन क्रू मॉड्यूल का एयर ड्रॉप टेस्ट सफल

नई दिल्ली। भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने रविवार (24 अगस्त, 2025) को पहला एकीकृत एयर ड्रॉप पैराशूट (IADT-01) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. गगनयान के लिए डिजाइन ये पैराशूट अंतरिक्ष यान की गति को कंट्रोल करने का एक सिस्टम है. ये परीक्षण अंतरिक्ष उड़ान पर गए यात्रियों के सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी के लिए किया गया है. परीक्षण के दौरान भारतीय वायु सेना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल उपस्थित रहे, जो इस मिशन के लिए सभी की एकता को दिखाता है. बता दें कि ये पैराशूट सिस्टम वायुमंडल में दोबारा प्रवेश के बाद क्रू मॉड्यूल के दोबारा सुरक्षित वापसी के लिए काफी जरूरी है. परीक्षण के दौरान, एक मॉक मॉड्यूल को विमान से छोड़ा गया और नव-विकसित पैराशूट असेंबली की मदद से सुरक्षित रूप से नीचे उतारा गया, जिससे ये परीक्षण सफल रहा. इसरो अधिकारियों के अनुसार, IADT-01 का उद्देश्य यह जांचना था कि पैराशूट खोलने की पूरी प्रक्रिया सही तरह से काम कर रही है या नहीं।

भारत के बाद अब यूरोप ने दिया ट्रंप को झटका

दो देशों ने US के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 खरीदने से कर दिया इनकार

भारत के बाद अब यूरोप से भी अमेरिका को बड़ा झटका लगा है. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की उम्मीदों को उस समय धक्का लगा, जब स्पेन और स्विट्जरलैंड ने अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 को खरीदने से साफ इनकार कर दिया. दोनों देशों ने इसके बजाय यूरोपीय विकल्पों पर भरोसा जताते हुए अपनी रक्षा रणनीति को नई दिशा दी है. स्पेन और स्विट्जरलैंड के हालिया फैसलों ने अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान से दूरी बनाने की ओर यूरोप के रुख को और स्पष्ट कर दिया है. यह कदम सिर्फ कीमतों पर विवाद की वजह से नहीं है, बल्कि अमेरिका के "सस्टेनमेंट मोनोपोली" को लेकर चिंता भी है, जिसमें भविष्य के सभी अपग्रेड, सॉफ़्टवेयर और ऑपरेशनल डेटा पर अमेरिका का नियंत्रण होगा. यह स्थिति बदलते राजनीतिक हालात में रणनीतिक जोखिम पैदा करती है.

स्पेन का चौंकाने वाला फैसला

स्पेन ने अचानक अपने F-35 खरीदने की योजना को खत्म कर दिया. पहले यह माना जा रहा था कि मैड्रिड अपनी नौसेना के Juan Carlos I एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए F-35B खरीदेगा, लेकिन अब उसने यह योजना रद्द कर दी है. इसके बजाय स्पेन ने 25 नए यूरोफाइटर टाइफून खरीदने और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम (FCAS) पर जोर देने का फैसला किया है.यह निर्णय स्पेन की नौसैनिक ताकत को फिलहाल कमजोर करेगा क्योंकि अब अगले दस साल तक उसके पास असली पांचवीं पीढ़ी का विमान नहीं होगा. लेकिन इसका फायदा घरेलू उद्योग को होगा. यूरोपीय प्रोग्राम्स में अरबों यूरो निवेश करके स्पेन अपनी सप्लाई चेन, रोजगार और तकनीकी क्षमता को मजबूत करेगा और यह सब यूरोपीय स्वामित्व में रहेगा.

स्विट्जरलैंड में बढ़ता असंतोष

स्विट्जरलैंड ने 2022 में जनमत संग्रह कराकर 36 F-35A विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी, जिसकी कीमत लगभग 6 अरब स्विस फ्रैंक थी. लेकिन 2023 के अंत तक हालात बदलने लगे. अमेरिका ने स्विस अधिकारियों को गुप्त ब्रीफिंग में बताया कि कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह फिक्स्ड नहीं है और महंगाई व सामग्री लागत बढ़ने पर कीमतें 650 मिलियन फ्रैंक या उससे ज्यादा बढ़ सकती हैं. इसके बाद वाशिंगटन ने स्विस निर्यात पर नए टैरिफ भी लगा दिए।

29 अगस्त से जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह शुक्रवार (29 अगस्त, 2025) को जापान और चीन की चार दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार (22 अगस्त, 2025) को प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित विदेश यात्रा के बारे में घोषणा की. पीएम मोदी अपनी विदेश यात्रा के पहले चरण में जापान की दो दिवसीय यात्रा पर रहेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री चीन की यात्रा करेंगे, जहां वह मुख्य रूप से शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री मोदी की दोनों एशियाई देशों की यात्रा की घोषणा चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के कुछ ही दिनों बाद हुई है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने पीएम मोदी की यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि मोदी 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन (India-Japan Annual Summit 2025) में भाग लेने के लिए 29 और 30 अगस्त को जापान में रहेंगे।

नोएडा के निक्की मर्डर केस में आरोपी पति का एनकाउंटर

पटना। मामले से जुड़े निक्की हत्याकांड में पत्नी को मारने वाले आरोपी पति विपिन की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है. पुलिस की इस मुठभेड़ में आरोपी विपिन के पैर में गोली लगने की खबर है. जानकारी के अनुसार आरोपी विपिन ने मेडिकल कराने के दौरान भागने की कोशिश की. वहीं विपिन के एनकाउंटर के बाद निक्की के पिता ने कहा कि विपिन के छाती में गोली मारनी चाहिए. दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी निक्की की हत्या के आरोपी विपिन भाटी ने कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है. मैंने उसे नहीं मारा है, वह खुद मर गई. पति-पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, यह बहुत आम बात है. वहीं आरोपी विपिन भाटी को पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है. ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे के पास विपिन का एनकाउंटर हुआ है, विपिन के पैर में गोली लगी है. विपिन के ऊपर अपनी पत्नी को जला कर मारने का आरोप है, आरोपी को मेडिकल के लिए पुलिस जा रही थी. इसी दौरान पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था विपिन और पुलिस का हथियार छीनने की कोशिश भी की थी।

भारत ने तैयार कर लिया अपना सुदर्शन चक्र

भारत ने ओडिशा तट से एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान परीक्षणों के लिए IADWS को विकसित करने वालों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और सशस्त्र बलों को बधाई दी. स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली का शनिवार देर रात साढ़े 12 बजे ओडिशा तट से उड़ान परीक्षण किया गया.

बहुस्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली है IADWS

नई हवाई रक्षा प्रणाली का उड़ान परीक्षण ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े तीन महीने बाद हुआ है. IADWS एक बहुस्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली है जिसमें त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने वाली सभी स्वदेशी मिसाइल, बहुत कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली (VSHORDS) मिसाइल और उच्च शक्ति वाली लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEW) प्रणाली शामिल हैं. राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा, 'मैं IADWS को सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए डीआरडीओ, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई देता हूं. इस अद्वितीय उड़ान परीक्षण ने हमारे देश की बहुस्तरीय हवाई रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और यह दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएगी.'

सुदर्शन चक्र में क्या है खास?

भारत का विकसित किया जा रहा उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम 'सुदर्शन चक्र' अपनी तकनीकी क्षमताओं के कारण बेहद खास है. यह सिस्टम 2500 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम होगा और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा में किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकेगा. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और लेजर-गाइडेड सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बेहद सटीक निशाना साधने की क्षमता देता है.

पुजारा ने लिया संन्यास

सोशल मीडिया पर पोस्ट कर की संन्यास की घोषणा

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की. उन्होंने एक भावुक पोस्ट करते लिखा, "भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना, और हर बार मैदान पर कदम रखते ही अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करना, इन चीजों को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है. लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी चीज का अंत होना ही होता है. मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है." चेतेश्वर पुजारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, "राजकोट के छोटे से कस्बे से एक छोटे से लड़के के रूप में, अपने माता-पिता के साथ, मैंने सितारों को निशाना बनाने का लक्ष्य रखा और भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने का सपना देखा. तब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि यह खेल मुझे इतना कुछ देगा. अमूल्य अवसर, अनुभव, उद्देश्य, प्यार, और सबसे बढ़कर अपने राज्य और इस महान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका. पुजारा ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "मैं बीसीसीआई और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को अपने क्रिकेट करियर के दौरान मिले अवसर और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. मैं उन सभी टीमों, फ्रैंचाइज़ियों और काउंटी टीमों का भी आभारी हूं जिनका मैंने इतने सालों तक प्रतिनिधित्व किया." पुजारा ने अपने करियर में मिले सभी टीमों के कोचों का भी आभार व्यक्त किया. चेतेश्वर पुजारा ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "खेल की वजह से मैं दुनियाभर में पहुंचा और इस दौरान प्रशंसकों का जोशीला समर्थन और ऊर्जा हमेशा मेरे साथ रही. जहाँ भी मैंने खेला है, वहां बहुत समर्थन मिला और हमेशा मैं इसका आभारी रहूंगा." यह सब मेरे परिवार, मेरे माता-पिता, पत्नी पूजा और बेटी अदिति, मेरे ससुराल वालों और मेरे बाकी परिवार के त्याग और सहयोग ने मेरे सफर को सार्थक बनाया. मैं अगले पड़ाव का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं."

चेतेश्वर पुजारा अंतर्राष्ट्रीय करियर

37 वर्षीय पुजारा ने अपने करियर में 103 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेले. 103 टेस्ट की 176 पारियों में पुजारा ने 7195 रन बनाए, इसमें 19 शतक और 35 अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं. पुजारा का टेस्ट सफर शानदार रहा, हालांकि वह काफी समय से टीम में वापसी नहीं कर पा रहे थे।

ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज की साल की सबसे बड़ी जीत

कैनबेरा। तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 276 रनों से हरा दिया है. ये वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की रनों के अंतर से दूसरी सबसे बड़ी जीत है. कंगारू टीम ने ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और कैमरून ग्रीन के शतकों की मदद से 431 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम सिर्फ 155 रनों पर सिमट गई. ये किसी टीम की वनडे में 2025 की सबसे बड़ी जीत है. ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 बल्लेबाज बैटिंग करने आए और चारों ने 50 या उससे ज्यादा स्कोर बनाया.

वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भारत के नाम है, जिसने 2023 में श्रीलंका को 317 रनों के अंतर से हराया था. अब ऑस्ट्रेलिया ने साल 2025 में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. इससे पहले 2025 में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम था, जिसने मई में वेस्टइंडीज को 238 रनों से हराया था. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज है, जिसने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान को 202 रनों से रौंदा था.

276 रन - ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका
238 रन - इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज
202 रन - वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान
197 रन - वेस्टइंडीज बनाम आयरलैंड
174 रन - श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के लिए चार बल्लेबाजों में से तीन ने शतक लगाया और एक ने अर्धशतक लगाया. ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श के बीच पहले विकेट के लिए 250 रनों की साझेदारी हुई. हेड ने 142 रन और कप्तान मार्श ने 100 रनों की पारी खेली. नंबर-3 पर बैटिंग करने आए कैमरून ग्रीन 55 गेंदों में 118 रन बनाकर नाबाद लौटे और एलेक्स कैरी ने भी नाबाद 50 रन बनाए. जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम लक्ष्य का पीछा करने आई तो डेवाल्ड ब्रेविस सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, उन्होंने 49 रनों की पारी खेली।

SMBC को Yes Bank में 24.99 परसेंट हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी

नई दिल्ली। जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) को यस बैंक में 24.99 परसेंट की हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही सोमवार को यस बैंक के शेयर फोकस में रहने वाले हैं. इससे पहले बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को NSE पर बैंक के शेयर 0.77 परसेंट गिरकर 19.28 रुपये प्रति शेयर पर आ गए. यस बैंक ने बीते 9 जुलाई, 2025 को जानकारी दी है कि SMBC सेकेंड्री मार्केट के जरिए बैंक में हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव रखा है. यह भारतीय स्टेट बैंक से 13.19 परसेंट हिस्सेदारी खरीदेगी. जबकि 6.81 परसेंट हिस्सेदारी सात अन्य शेयरहोल्डर्स से खरीदेगी. अन्य शेयरधारकों में एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं।

SBI के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को माना फ्रॉड

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया (BoI) ने भी कर्ज में डूबी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के लोन अकाउंट को फ्रॉड करार दिया है और 2016 में कथित तौर पर फंड के डायवर्जन का हवाला देते हुए कंपनी के पूर्व डायरेक्टर अनिल अंबानी का भी नाम लिया है. रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी गई है. इससे पहले इस साल जून में भारतीय स्टेट बैंक ने भी इसी तरह का कदम उठाया था. SBI ने RCom पर लोन लेने की शर्तों का उल्लंघन कर पैसों की हेराफेरी करने का आरोप लगाया था.

BOI से मिले लोन का कंपनी ने क्या किया?

शेयर बाजार को दी गई जानकारी में RCom ने कहा है, कंपनी को 22 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया से एक पत्र मिला, जिसमें कंपनी के प्रमोटर और पूर्व डायरेक्टर अनिल धीरजलाल अंबानी और कंपनी की एक और पूर्व डायरेक्टर मंजरी अशोक कक्कड़ के लोन अकाउंट को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की जानकारी दी गई थी. बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2016 में कंपनी को चलाने और पहले लिए गए कर्ज का भुगतान करने के लिए RCom के लिए 700 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दी थी. हालांकि, बैंक ने आरकॉम द्वारा जारी अपने पत्र में कहा कि लोन के रूप में मिले इन पैसों में से आधे का निवेश फिक्स्ड डिपॉजिट में किया गया था, जो लोन मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन है. एसबीआई की शिकायत के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शनिवार को आरकॉम और अंबानी के आवास से जुड़े परिसरों की तलाशी ली. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय स्टेट बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी द्वारा की गई कथित हेराफेरी के चलते 2,929.05 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया है।

एशिया कप में टॉप आर्डर में नहीं खेलेंगे संजू सैमसन

नई दिल्ली। संजू सैमसन पिछले कई समय से टी20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कर रहे थे, जिसके बाद माना जा रहा था कि एशिया कप में भी वह इसी पोजीशन पर खेलेंगे. पिछली 10 टी20 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में संजू सैमसन ने 3 शतक जड़े, हालांकि बाकी पारियां ज्यादा अच्छी नहीं रही लेकिन उन्हें एशिया कप में इस पोजीशन का बड़ा दावेदार माना जा रहा था. लेकिन टीम मैनेजमेंट की सोच कुछ अलग है. शुभमन गिल अब ओपनिंग करेंगे, हालांकि संजू ने नई पोजीशन के लिए तैयारी शुरू कर दी है लेकिन पहले प्रयास में वह फेल रहे. चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम एलान के समय साफ़ किया था कि संजू सैमसन इसलिए ओपनिंग कर रहे थे क्योंकि शुभमन गिल टीम में नहीं थे, अब वह वापस आ गए हैं. यानी पूरी संभावना है कि गिल और अभिषेक शर्मा एशिया कप में पारी की शुरुआत करेंगे. तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा और चौथे नंबर पर सूर्यकुमार यादव आएंगे. पांचवे नंबर पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर सकते हैं, इसलिए विकेट कीपर बल्लेबाज सैमसन के लिए छठे नंबर का स्लॉट खाली रहेगा.

Dream11 के साथ BCCI की करोड़ों की डील खतरे में?

नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा लाए गए नए ऑनलाइन गेमिंग बिल (Online Gaming Bill 2025) को अब कानून का रूप मिल गया है. इसका सबसे ज्यादा असर ऑनलाइन गेमिंग प्लैटफॉर्म ड्रीम 11 पर पड़ता दिख रहा है. ये वही कंपनी है, जिसका लोगो साल 2023 से टीम इंडिया की जर्सी पर छपा हुआ दिख रहा है. एक तरफ ऑनलाइन गेमिंग पर कानून बन गया है, ऐसे में ड्रीम11 और BCCI की डील का क्या होगा और उनके बीच आखिर कितने करोड़ रुपयों की डील हुई थी. बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया साफ कर चुके हैं कि इस नए कानून का बोर्ड पूरा समर्थन करता है. बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग पर बने इस नए कानून से उन सभी प्लैटफॉर्म पर असर पड़ेगा, जिनमें असली पैसे का लेन-दें होता है।

क्या जीएसटी रिफॉर्म्स से सोने की कम होंगी कीमतें?

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक सितंबर महीने के पहले हफ्ते में होगी. इससे तरह-तरह की चीजों और सर्विसेज की कीमतें कम होने की उम्मीद है. पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की जनता को संबोधित करते हुए जीएसटी स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स का ऐलान किया था, जिससे आम आदमी को काफी राहत मिलने की उम्मीद है. नए प्रस्ताव के मुताबिक, नए जीएसटी स्ट्रक्चर में सिर्फ दो ही- 5 परसेंट और 18 परसेंट स्लैब होंगे.

सोने की बढ़ेगी या घटेगी कीमत?

मौजूदा समय में सोने पर 3 परसेंट की दर से जीएसटी वसूला जाता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने पर लगने वाली जीएसटी में 0.5 परसेंट से 1 परसेंट की कटौती की जा सकती है. हालांकि, कारोबारियों को इस बात की आशंका है कि कहीं इसे बढ़ाकर 5 परसेंट न कर दिया जाए. इससे आम आदमी का बजट गड़बड़ा सकता है इसलिए उनकी मांग सोने पर जीएसटी बढ़ाने के बजाय इसे कम करना है. अगर सरकार सोने पर जीएसटी कम करती है, तो इससे कीमतें सस्ती होंगी. ऐसे में फेस्टिव सीजन के दौरान मांग बढ़ने की संभावना है.

बढ़ती कीमतों के बीच जीएसटी में होगा इजाफा?

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वाइस प्रेसिडेंट और एस्पेक्ट ग्लोबल वेंचर्स की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अक्षा कंबोज ने गुडरिटर्न्स से बात करते हुए कहा, चूंकि सोने के आभूषण निवेश के रूप में या किसी खास मौके पर खरीदे जाते हैं इसलिए जीएसटी में थोड़ी सी भी कटौती होने पर उपभोक्ताओं पर खर्च का बोझ कम होगा. सोने पर फिलहाल जीएसटी रेट 3 परसेंट है. इसमें केंद्र सरकार की 1.5 परसेंट और राज्य सरकार की 1.5 परसेंट की हिस्सेदारी है. जीएसटी सोने की ज्वेलरी से लेकर बार, सिक्के सभी में लगाई जाती है. 2016 में भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया. उस दौरान सोने पर 3 परसेंट जीएसटी लगाई गई. इससे पहले तक ज्वेलरी पर 1 परसेंट वैट लगता था. बीते छह महीने में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है, इससे लोग पहले से ही परेशान है. ऊपर से अगर सोने पर जीएसटी कम होने के बजाय इसे बढ़ा दिया जाता है, तो आम आदमी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है.

3-4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी. इसमें केंद्र सरकार के तीन स्तंभ वाले जीएसटी रिफॉर्म्स पर चर्चा होगी. जीएसटी 2.0 में टैक्स की दरों में बड़े पैमाने पर किया गया बदलाव शामिल है. जीएसटी स्ट्रक्चर में किए गए सुधार और आम आदमी को मिलने वाली राहत के अलावा काउंसिल सरकार द्वारा प्रस्तावित 2-रेट जीएसटी स्ट्रक्चर पर भी सोच-विचार करेगी. गौरतलब है कि जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत 12 परसेंट और 28 परसेंट स्लैब को 5 परसेंट और 18 परसेंट के स्लैब में शामिल कर लिए जाने के प्रस्ताव को GoM ने मंजूरी दे दी है. अब इस पर काउंसिल की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा. सरकार ने शराब, जुआ, तंबाकू जैसे सिनफुल गुड्स पर 40 परसेंट की दर से जीएसटी लगाए जाने का भी प्रस्ताव रखा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर परजीएसटी दरों को कम करने का वादा किया था।

विदेश में भी छत्तीसगढ़ की समृद्धि की प्रार्थना

मुख्यमंत्री श्री साय और उनके प्रतिनिधिमंडल की ये यात्रा उपलब्धियों से परिपूर्ण है। इसमें व्यापार, तकनीक और कूटनीति से जुड़े अहम अवसरों की खोज की गई। इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ को तीव्र औद्योगिक विकास, डिजिटल नवाचार और वैश्विक साझेदारी के एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। जापान और कोरिया की यह यात्रा निश्चित ही सांस्कृतिक रिश्तों और व्यापारिक साझेदारी को मजबूती के साथ ही वैश्विक सेतु निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आर्थिक स्थिरता, व्यापारिक सुरक्षा, पारिस्थितिकीय संतुलन और औद्योगिक वृद्धि की अहम भूमिका है। जापान की उन्नत तकनीक और भारत के कुशल जनशक्ति के संयोजन से व्यापक औद्योगिक सहयोग की संभावनाएँ हैं।

रायपुर। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), भारत सरकार के आमंत्रण पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान और दक्षिण कोरिया के आधिकारिक दौरे पर है। इस यात्रा का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेश मानचित्र पर स्थापित करना है।

टोक्यो (22-24 अगस्त) में प्रतिनिधिमंडल जापानी उद्योगपतियों, व्यापार संघों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर कनेक्ट सेशंस एवं व्यावसायिक बैठकों में भाग लेगा। इसके बाद ओसाका (25-26 अगस्त) में मुख्यमंत्री श्री साय वल्र्ड एक्सपो 2025 में शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ में निवेश अवसरों पर विभिन्न हितधारकों से चर्चा करेंगे। दौरे का अंतिम चरण सियोल (27-29 अगस्त) में होगा, जहाँ निवेशक गोलमेज बैठकों, कोरिया की शीर्ष कंपनियों और व्यापार संघों से मुलाकात तथा सेक्टर-विशेष संवाद आयोजित किए जाएंगे।

टोक्यो के प्राचीन असाकुसा मंदिर पहुंचे सीएम साय,छग की 3 करोड़ जनता की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना की

शहर सत्ता/टोक्यो-रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान पहुंचने के बाद सबसे पहले जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर के दर्शन किए। टोक्यो का यह सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर शांति और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की खुशहाली, समृद्धि और निरंतर प्रगति की कामना की। उन्होंने कहा कि यह मंदिर मानवता को शांति और शक्ति का संदेश देता है और यही भाव छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं में भी झलकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO), भारत सरकार के आमंत्रण पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर है। इस ग्लोबल आउटरीच मिशन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेश मानचित्र पर स्थापित करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए अवसरों को तलाशना है।

वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ पर फोकस

ओसाका में आयोजित वल्र्ड एक्सपो 2025 में भारत मंडपम अंतर्गत छत्तीसगढ़ पवेलियन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत, नवाचार की संस्कृति और उभरते भविष्य-उन्मुख क्षेत्रों को वैश्विक दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पवेलियन को राज्य की अनूठी पहचान को दर्शाने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। इसमें औद्योगिक विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे प्रमुख फोकस क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि यह प्रदर्शनी पूरी दुनिया के लिए छत्तीसगढ़ के परिवर्तन और भविष्य की आकांक्षाओं की झलक प्रस्तुत करेगी।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जापान और कोरिया के उद्योगपतियों, व्यापार संघों और वैश्विक निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक साझेदारियाँ स्थापित करना, नए व्यापारिक चैनल खोलना तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में ज्ञान आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

विश्व के सबसे बड़े नवाचार और सहयोग प्लेटफार्मों में से एक में भाग लेकर मुख्यमंत्री श्री साय इस अवसर का उपयोग इस्पात, खनन, स्वच्छ ऊर्जा और स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए करेंगे। यह मिशन राज्य की सक्रिय पहल को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाना और आर्थिक विकास के नए अवसरों को खोलना है।

जापान में निवेश से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक को सुदृढ़ करने प्रयास

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अपने सतत प्रयासों के माध्यम से स्वयं को वैश्विक मंच पर एक प्रतिस्पर्धी एवं दूरदर्शी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान प्रवास के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ में औद्योगिक सहयोग तथा वैश्विक साझेदारियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। इस क्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में क्षेत्रीय विविधीकरण, व्यापार एवं तकनीकी सहयोग, आधारभूत संरचना विकास तथा छत्तीसगढ़ में उभरते निवेश अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर राज्य की निवेशक-अनुकूल नीतियों, हाल के सुधारों तथा स्टार्टअप्स और नई पीढ़ी के उद्योगों को प्रदान किए जा रहे सशक्त सहयोग पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ के भविष्य की दिशा तय करने में उन्नत प्रौद्योगिकियों की महत्ता पर बल देते हुए टोक्यो में आयोजित डीप स्पेश टू द मून एंड वीयांड नामक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

जापान में सुशासन सरकार; निवेश और नवाचार की दिशा में ठोस कदम

जेट्रो के साथ बैठक में छत्तीसगढ़ के आईटी, टेक्सटाइल्स और एयरोस्पेस अवसरों पर हुई चर्चा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान टोक्यो में जापान एक्सटर्नल ट्रेड आर्गनाइजेशन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों नाकाजो काज़ुया, एंडो युजी और हारा हारुनोबू से भेंट कर निवेश एवं औद्योगिक सहयोग के संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में आईटी, टेक्सटाइल्स, एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया गया। मुख्यमंत्री ने जेट्रो के प्रतिनिधियों को प्रदेश की तेज़ी से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्था में निवेश के नए अवसर तलाशने हेतु आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़, भारत के हृदय स्थल में स्थित एक उभरता हुआ औद्योगिक एवं निवेश गंतव्य है। राज्य सरकार पारदर्शी नीतियों, सुगम प्रक्रियाओं और मजबूत औद्योगिक आधारभूत संरचना के माध्यम से वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर रही है। जेट्रो प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा से छत्तीसगढ़ और जापान के बीच आर्थिक सहयोग की नई संभावनाओं को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आयोजित डीप स्पेश टू द मून एंड बिआएंड प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान और नवाचारों की यह समृद्ध झलक, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में भारत सरकार के सहयोग से विकसित किए जा रहे स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को नई दिशा और प्रेरणा देगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि जापान प्रवास से छत्तीसगढ़ को निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में ठोस परिणाम प्राप्त होंगे।

खनन क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में 15 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व

नए खनन प्रोजेक्ट से छत्तीसगढ़ के विकास को मिली नई गति

शहर सत्ता/रायपुर। राज्य स्तरीय भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल छत्तीसगढ़ की रजत महोत्सव के रूप में 25वी बैठक सिविल लाईन स्थित न्यू सर्किट हाउस में पी. दयानंद, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में रजत बंसल, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य शासन के विभिन्न विभागो, उपक्रमों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग, नए खनन परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करना और गत वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा करना रहा।

बैठक में वर्ष 2024-25 के दौरान पूरे हुए खनन कार्यों और उनसे प्राप्त उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश को खनिज राजस्व के रूप में लगभग 15 हजार करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। यह उपलब्धि वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 34 प्रतिशत अधिक है। इस वृद्धि ने न केवल प्रदेश के आर्थिक ढांचे को मजबूती दी है, बल्कि खनन क्षेत्र में नए निवेश और अवसरों के द्वार खोले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज अन्वेषण एवं खनिज दोहन के क्षेत्र में कार्यरत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों एवं संस्थानों के द्वारा वर्ष 2024-25 में किये गये भू-वैज्ञानिक कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जहां वर्ष 2024-25 के सम्पादित कार्यों की उपलब्धियों पर चर्चा की गई वही प्रदेश में पाये जाने वाले खनिजों की खोज के लिए वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित भू-वैज्ञानिक कार्यों को अंतिम रूप दिया गया।

बैठक में संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ श्री रजत बंसल के द्वारा क्षेत्रीय सत्र 2024-25 में सम्पन्न कार्यों की जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्ष 2024-25 में लगभग 2500 मिलियन टन चूनापत्थर एवं लौह अयस्क के लगभग 93 मिलियन टन भण्डार आंकलित किये गये। आगामी क्षेत्रीय सत्र 2025-26 के अन्वेषण परियोजनाओं में विभाग द्वारा महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों को शामिल किया गया है। यह परियोजना देश के लिए आवश्यक खनिज संसाधनों की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा। यह आत्मनिर्भर भारत मिशन को सशक्त करेगी। "छत्तीसगढ़ शासन वैज्ञानिक एवं विस्तृत खनिज अन्वेषण तथा विकास को पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

प्रदेश में अब तक 783.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 783.0 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 1157.4 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 397.8 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 689.8 मि.मी., बलौदाबाजार में 596.1 मि.मी., गरियाबंद में 684.3 मि.मी., महासमुंद में 610.5 मि.मी. और धमतरी में 702.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 780.8 मि.मी., मुंगेली में 778.6 मि.मी., रायगढ़ में 921.0 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 662.3 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 971.4 मि.मी., सक्ती में 832.0 मि.मी., कोरबा में 781.8 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 728.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 649.0 मि.मी., कबीरधाम में 564.6 मि.मी., राजनांदगांव में 720.8 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1020.8 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 577.5 मि.मी. और बालोद में 840.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 544.7 मि.मी., सूरजपुर में 881.9 मि.मी., जशपुर में 790.7 मि.मी., कोरिया में 872.8 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 774.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बस्तर संभाग में बस्तर जिले में 1017.6 मि.मी., कोंडागांव में 723.8 मि.मी., कांकेर में 928.7 मि.मी., नारायणपुर में 939.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

बीएआई के मंच से बोले डिप्टी सीएम साव, जीएसटी भुगतान समेत अन्य समस्याओं का होगा समाधान

शहर सत्ता/रायपुर। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) की दो दिवसीय बैठक के दूसरे दिन आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिल्डरों को आश्वासन दिया कि राज्य से होने वाले कार्यों में GST का भुगतान अलग से किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिल्डरों और ठेकेदारों की अन्य समस्याओं का भी शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से PWD विभाग के मुख्य अभियंता स्तर की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। दो दिवसीय कार्यक्रम में MSME क्षेत्र में आ रही चुनौतियों और EPF भुगतान में कई राज्यों में हो रही देरी के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। एसोसिएशन ने मांग की है कि इन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शासन विशेष नीति बनाए।

पैरासिटामोल दवा की खेप में मिली गुणवत्ता की कमी

सीजीएमएससी ने दिया कंपनी को नोटिस, होगी कार्रवाई

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSCL) ने महासमुंद स्थित 9M इंडिया लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई 2024 की विभिन्न खेपों में पैरासिटामोल 500 एमजी और 650 एमजी टैबलेट की गुणवत्ता में प्रथम दृष्टया कमी पाई गई है। निगम के दवा गोदामों और स्वास्थ्य इकाइयों से मिली शिकायतों के बाद वर्ष 2024 में निर्मित बैचों की जांच कराई गई हैं।

CGMSCL की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि संबंधित बैच की दवाइयों की गुणवत्ता में कमी है और उन पर काले धब्बे पाए गए हैं जो आम के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसके बाद निगम ने आदेश जारी करते हुए कंपनी को नागरिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सभी संदिग्ध बैच तत्काल दवा गोदामों और स्वास्थ्य संस्थाओं से वापस लेने और उसकी जगह गुणवत्तापूर्ण नई खेप उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि कंपनी ने तय शर्तों के अनुरूप कार्यवाही नहीं की, तो निविदा नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कंपनी की होगी।

ड्रोन तकनीक से नैनो यूरिया का छिड़काव

रायपुर। प्रदेश में किसान खेती-किसानी में नई तकनीकों को अपना रहे हैं। महासमुंद जिले के ग्राम जोगनीपाली में शनिवार को किसानों के बीच ड्रोन तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव कर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर अधिकारीयों ने किसानों को पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया के लाभों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। किसानों को नैनो यूरिया के प्रयोग से लागत में कमी, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि और पर्यावरणीय लाभों के बारे में अवगत कराया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के वरिष्ठ किसान श्री अमृत पटेल, भोगलाल चौधरी, नेहरू चौधरी, चुम्बन लाल सहित लगभग 30 किसान उपस्थित रहे।

166 महतारी सदन हेतु 49 करोड़ 80 लाख रुपये जारी

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक महतारी सदन

प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने सामायिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार महतारी सदन का निर्माण कार्य किया जाना है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयास से 166 महतारी सदन की स्वीकृति आदेश जारी किया गया है, इसके लिए 49 करोड़ 80 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बनने जा रहा महतारी सदन भी इसी दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि लगातार ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं द्वारा बैठने की स्थान न होने की शिकायत की और बैठने हेतु स्थान दिलाने की मांग की जाती रही इसलिए महतारी सदन बनाने का विचार आया। ततपश्चात महिलाओं को रोजगार दिलाने और उनको काम काज के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार गांवों में महतारी सदन बनाने जा रही है। अब तक 368 महतारी सदन की स्वीकृति इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिये जारी किया गया है। कार्यों में एकरूपता के दृष्टिकोण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य का एक मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन तैयार किया गया है। प्रति महतारी सदन की लागत राशि रुपये 30 लाख होगी।

5 वर्षों में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने की योजना

प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाया जाएगा। महतारी सदन बनाने की शुरुआत हो गयी है। पहले चरण में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में महतारी सदन बनना प्रारंभ किया जा रहा है व 5 साल में सभी ग्राम पंचायत में महतारी सदन बनेंगे। प्रदेश में बनने वाले महतारी सदन का निर्माण लगभग 25 सौ वर्गफुट में कराया जाएगा। सदन में कमरा, शौचालय, बरामदा, हाल, किचन और स्टोररूम जैसी सुविधाएं रहेंगी। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा।

साप्ताहिक शहर सत्ता

नेता प्रतिपक्ष महंत बोले- CG में अनुभवहीन सरकार

14 मंत्रियों पर कहा- संविधान का पालन नहीं हुआ तो कोर्ट जाएंगे

शहर सत्ता/जीपीएम/रायपुर। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में महंत ने कहा कि, प्रदेश में अनुभवहीन सरकार है। अनुभवहीन लोगों को मंत्री बना दिया गया है। नए मंत्री अभी तक विधायक का काम भी ठीक से नहीं सीख पाए हैं। ऐसे में वे मंत्री का काम कैसे करेंगे।

14 मंत्री बनाने पर भी महंत ने सवाल उठाए। उन्होंने उपमुख्यमंत्री अरुण साव के बयान का जवाब देते हुए कहा कि साव खुद वकील हैं। उन्हें संविधान का पालन करना चाहिए। महंत ने हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी 90 विधानसभा सीटों पर 14 मंत्रियों का मामला कोर्ट में है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर संविधान का पालन नहीं हुआ तो वे कोर्ट जाएंगे।

सांसद ज्योत्सना महंत ने भी सरकार पर साधा निशाना

कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में कई संगठन हड़ताल पर हैं। सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के कार्यकाल में क्या हो रहा है, यह समझ से परे है। राज्य की समस्याओं को संसद में उठाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि, अपने मतदाताओं और अपनी जनता की समस्या को लेकर मैं संसद में बोलना चाहती हूं, तो बोलते नहीं दिया जाता। माइक बंद कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि संविधान तो छोड़िए अब पहले देश बचाना है तभी तो हमारी मतदाता बचेंगे। प्रदेश में 14 मंत्री को लेकर कहा कि, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री से लेना चाहिए।

साय मंत्रिमंडल विस्तार को पूर्व सीएम ने बताया असंवैधानिक और ग़लत

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में कल हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार असंवैधानिक और ग़लत है. उन्होंने कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 164(1A) का उल्लंघन है और माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय का भी. उन्होंने कहा है कि यदि राज्य सरकार ने इसकी विधिवत अनुमति नहीं ली है तो एक मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर प्रदेश में 14 वें मंत्री को शपथ दिलाई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक अतिरिक्त सदस्य को शपथ दिलाना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है इसलिए इस मंत्रिमंडल विस्तार को तत्काल निरस्त करना चाहिए.अगर इसके लिए केंद्र सरकार या किसी उपयुक्त अदालत से अनुमति ली गई हो तो इस अनुमति को सार्वजनिक करना चाहिए। चूंकि मुख्यमंत्री साय की ओर से अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है इसलिए प्रतीत होता है कि यह असंवैधानिक है। विधान की के अनुच्छेद 164 में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के तहत संशोधन किया गया था। यह परिवर्तन 1 जनवरी, 2004 से प्रभावी हुआ। इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 164 में खंड (1A) और (1B) जोड़े गए। विभिन्न राज्यों में बढ़ते मंत्रिमंडल के आकार और दल-बदल की घटनाओं के कारण इस संविधान संशोधन की आवश्यकता को महसूस किया गया था।

संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर शहर कांग्रेस की बैठक

मंडल अध्यक्षों के नामों पर हुई चर्चा, डहरिया और विजय जांगिड़ रहे मौजूद

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी विजय जांगिड़ और पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न ब्लॉकों से प्राप्त मंडल अध्यक्षों के प्रस्तावित नामों पर चर्चा की गई। इस दौरान निर्देश दिया गया कि सभी प्रस्तावित नामों को जल्द से जल्द जिला अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को भेजा जाए, ताकि तय समय सीमा के भीतर मंडल और सेक्टर समितियों का गठन किया जा सके। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गिरीश दुबे, विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, पंकज शर्मा, दीपक दुबे, कन्हैया अग्रवाल, शैलेश नितिन त्रिवेदी, महेंद्र छाबड़ा, अजय साहू, प्रवीण साहू, ममता राय सहित समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे।

एससी-एसटी और ओबीसी के लिए अलग संचालनालय बनाने की तैयारी

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ गठन के ढाई दशकों बाद राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अलग से दिया है। प्रदेश में लगभग 1.25 करोड़ ओबीसी है। इस विभाग की कमान श्याम बिहारी जायसवाल को सौंपी गई है। अब मंत्रालय में मंथन चल रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग -अल्पसंख्यक विभाग, आदिम जाति विकास विभाग तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के लिए अलग-अलग संचालनालय बनाए जाएं।

वर्तमान में इन विभागों के प्रमुख सचिव सोनमणि हैं। तीन अलग-अलग विभाग बंट जाने से उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। यदि तीन अलग-अलग संचालनालय बनाए जाते हैं तो फाइलों के मूवमेंट, बजट आबंटन और स्टाफ बंटवारे में प्रारंभिक दिक्कतें होंगी। सरकार ओबीसी वर्ग पर फोकस कर रही है। सबसे ज्यादा शिकायत छात्रवृत्ति और जाति प्रमाणपत्र बनाने को लेकर आती है। एससी-एसटी को छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं वाली योजनाओं पर ही सरकार ध्यान देती रही है। ओबीसी वर्ग के एक जिम्मेदार का कहना है कि उनका समाज वर्ष 2020 से ही अलग मंत्रालय की मांग कर रहा था। अब ओबीसी विभाग श्याम बिहारी जायसवाल, अनुसूचित जाति विकास विभाग नए मंत्री गुरु खुशवंत साहेब और ट्राइबल विभाग वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम के पास रहेगा। अगले साल से प्रदेश में जनगणना होगी। इसमें जाति जनगणना भी होगी। तब सभी वर्गों के आंकड़े सामने आ जाएंगे।

भूपेश सरकार का फैसला

एसटी, एससी और ओबीसी विभाग को अलग करने का फैसला कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने लिया था। केबिनेट की बैठक में 6 सितंबर 2022 को इन वर्गों के लिए सलाहकार परिषदें बनाने का भी निर्णय हुआ था। तीनों परिषदों की कमान सीएम के हाथ रखने, विभागों के मंत्रियों को उपाध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति बनी थी। ओबीसी परिषद में 10 विधायकों समेत 40 सदस्य, अनुसूचित जाति परिषद में इस वर्ग के 5 विधायकों समेत 20 सदस्य बनाए जाने का प्रावधान किया गया था। जनजातीय सलाहकार परिषद पहले से ही काम कर रही थी। तीनों के संचालनालय भी अलग किए जाने थे। पिछली सरकार के इस

उप राष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर भाजपा ने साधा निशाना

शहर सत्ता/रायपुर। इंडी गठबंधन के उप राष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर भाजपा ने निशाना साधा है। प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग करके रेड्डी को वामपंथी नक्सलियों का समर्थक बताया है। ठाकुर ने रेड्डी को वामपंथी नक्सलियों का समर्थक बताया है। उन्होंने कहा, कांग्रेसनीत विपक्ष ने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद को मदद करने के लिए सलवा जुडूम के खिलाफ जजमेंट दिया था। ऐसा नहीं होता तो वामपंथी नक्सलवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। ठाकुर ने कहा कि रेड्डी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने से आदिवासी समुदाय उद्वेलित हैं। एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का हाथ हमेशा नक्सलियों के साथ है। कांग्रेस के लोगों को देश व प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कांग्रेस पर हमला बोला है। पंकज झा ने लिखा कि आश्चर्य है कि अर्बन नक्सलियों के मुकदमे के पक्ष में निर्णय देकर आदिवासियों की प्राण ले लेने वाले तब के जज को आज कांग्रेस इस तरह सम्मानित कर रही है।

मंत्रिमंडल के विभाग फेर बदल में गृहमंत्री भी बदलना था

भाजपा सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था बदहाल हो गयी है

शहर सत्ता/रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मंत्रिमंडल के विभाग फेर बदल में गृहमंत्री भी बदलना था। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा गृह विभाग संभाल नहीं पा रहे है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा 20 महीने में परफॉर्मेंस दिखाने में असफल साबित हो गए हैं। आए दिन हत्या चाकूबाजी, लूटपाट, डकैती, अपहरण, बलात्कार, गोलीबारी की घटनाएं हो रही है, नशीली दवाइयों की तस्करी बढ़ गई है, जेल में भी आपराधिक बेलगाम हो रही हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है, अपराधी अनियंत्रित हो गये है। मुख्यमंत्री को उनसे गृह विभाग वापस लेकर किसी अन्य को देना था, ताकि प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि गृह मंत्री की अकर्मण्यता के कारण अपराधिक तत्व इतने बेखौफ हो गये है कि उनमें पुलिस का भय जरा भी नहीं बचा है। राह चलते किसी को भी चाकू मार दी जा रही, सड़कों पर खुलेआम हत्या हो रही

है। प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है राजधानी में सरेआम गोलीबारी की पांच घटनाएं हो चुकी है। सरकार की नाकामी और पुलिस की लापरवाही का परिणाम है कि प्रदेश की राजधानी असुरक्षित हो चुकी है। राजधानी रायपुर चाकूपुर बन गया है। प्रदेश के लगभग सभी शहरों में रोज ही हत्याएं हो रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में कानून व्यवस्था है ही नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था सुधारने के लिये कोई निर्णय नहीं ले रहे है। सरकार अपराधियों पर लगाम कसने के बजाय उनकी संरक्षक बन गयी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था दिनोदिन और बिगड़ते जा रही है और सरकार मूकबधिर बनकर बैठी हुई है अब तो हत्या, अपराध की घटनाये बर्दाशत के बाहर हो गयी है। सरकार निकम्मी और लाचार बन गयी है मुख्यमंत्री से सरकार नही संभल रहा, गृहमंत्री से गृह विभाग नही संभल रहा है।

शर्मा से गृह, एवं पंचायत विभाग भी ले लेना था : धनंजय सिंह

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा कोई भी विभाग संभाल नहीं पा रहे है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा 20 महीने में परफॉर्मेंस दिखने में असफल हो गए हैं। मंत्री विस्तार के उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा से तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग वापस लेने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ दो उपमुख्यमंत्री बनाए गए थे, उनमें से विजय शर्मा से मुख्यमंत्री ने तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को वापस लेकर उनके पर कतर दिए।

छत्तीसगढ़ का स्वर्ग

शिमला-मनाली का आनंद

सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक विरासत और जनजातीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा यह क्षेत्र घने जंगलों, मनोहारी जलप्रपातों और प्राचीन गुफाओं का घर है। अंबिकापुर जैसे वाणिज्यिक केंद्र से लेकर रामायण युग से जुड़े स्थलों तक, सरगुजा विविधता और सांस्कृतिक गहराई में बेजोड़ है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने इस जिले को पर्यटन नक्शे पर उभारने की दिशा में नई ऊर्जा और योजनाओं के साथ कदम आगे बढ़ाया है।

सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाएँ

सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में स्थित रामगढ़ की पहाड़ियाँ ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। यहीं से महाकवि कालिदास को "मेघदूत" के लिए प्रेरणा मिली थी। इसी पहाड़ी पर स्थित सीता बेंगरा गुफा भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशालाओं में एक मानी जाती है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की यह गुफा ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों से युक्त है। पास ही स्थित जोगीमारा गुफा अपने भित्तिचित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रेम, नृत्य और वन्य जीवन के चित्रण से समृद्ध हैं। यहाँ हर वर्ष आयोजित होने वाला "कालिदास महोत्सव" साहित्य, कला और संस्कृति का जीवंत मंच बन चुका है। पर्यटकों के लिए ट्रेकिंग मार्ग, सूचना केंद्र, गाइड सुविधा और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसे पूरे साल आकर्षक बनाए रखते हैं।

टाइगर पॉइंट

यह एक ऊँचाई से गिरने वाला खूबसूरत जलप्रपात है, जो जंगलों और घाटियों के मध्य स्थित है। यहाँ से नीचे की ओर बहता झरना टाइगर की दहाड़ जैसी गूंज करता है, इसी कारण इसे 'टाइगर पॉइंट' कहा जाता है। मानसून और उसके बाद (जुलाई से दिसंबर) का समय इस स्थान की खूबसूरती को चरम पर ले आता है। यहाँ की ठंडी हवा, हरियाली और झरने की आवाज मन मोह लेती है। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए यह आदर्श स्थल है। बैठने की जगह, रुकने के लिए विश्राम स्थल, और हाल ही में सुरक्षा रेलिंग का निर्माण हुआ है।

सेमरसोत अभयारण्य

अंबिकापुर से 45 किमी दूर स्थित यह अभयारण्य तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली सूअर जैसी वन्य प्रजातियों का घर है। 1978 में स्थापित इस अभयारण्य में सफारी, बर्ड वॉचिंग और नेचर ट्रेल्स का अनुभव लिया जा सकता है। वन विभाग द्वारा वॉच टावर, पर्यटक विश्रामगृह और गाइड सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है, जिससे यह ईको टूरिज्म का महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है।

ठिनठिनी पत्थर

अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर स्थित ठिनठिनी पत्थर एक विशाल चट्टान है, जो बजाने पर घंटी जैसी आवाज करती है। यह स्थल बच्चों और भूगोल प्रेमियों के बीच खासा लोकप्रिय है। यहाँ सूचना बोर्ड, बैठने की सुविधा और स्थानीय दुकानें उपलब्ध कराई गई हैं।

बाँका जलप्रपात

मानसून का सौंदर्य सीतापुर के समीप स्थित यह जलप्रपात अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बरसात के मौसम में यह अपने पूर्ण वैभव में होता है और पिकनिक के लिए आदर्श स्थल है। सरकार इसे परिवारों और युवाओं के लिए ईको-फ्रेंडली पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है।

तातापानी : प्राकृतिक गर्म जलकुंड

अंबिकापुर से महज 12 किमी दूर स्थित तातापानी अपने प्राकृतिक गर्म जल स्रोतों के लिए जाना जाता है। इन झरनों का तापमान और औषधीय गुण इसे स्वास्थ्य पर्यटन का केंद्र बनाते हैं। यहाँ स्नान के लिए कुंड, मंदिर, चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएँ विकसित की गई हैं। शिवरात्रि और मकर संक्रांति के समय श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। सरकार इस स्थल को आधुनिक स्वास्थ्य और धार्मिक पर्यटन केंद्र में बदलने की दिशा में काम कर रही है।

छग; सेवानिवृत्ति की मेवावृत्ति ...

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक भ्रष्टाचार की एक बड़ी वजह प्रभारवाद को माना जाता है। सेवानिवृत्ति की मेवावृत्ति वाले ऐसे अफसरों के 25 साल में कई उदहारण हैं। सूबे में प्रभारवाद की बीमारी 2013 के बाद तेजी से पनपी। शुरू में पीडब्लूडी, इरीगेशन और पीएचई के ईएनसी से चालू हुई। तब सीनियर अफसरों के होते जूनियरों को चीफ बनाया जाने लगा। दरअसल, पूर्णकालिक अफसर एक लिमिट से अधिक कंप्रोमाइज नहीं करता। मगर प्रभारी कुछ भी कर सकता है। उसे लगता है कि किसी भी दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी। इसका फायदा यह होता है कि उससे जहां चाहे, वहां दस्तखत करा लो। सरकार अगर प्रभारवाद सिस्टम को खतम कर दें तो छत्तीसगढ़ में 25 प्रतिशत करप्शन एक झटके में खतम हो जाएगा। उदाहरण के लिए सितंबर माह तक एक्सटेंशन प्राप्त सीएस फ़िलहाल सीएम संग विदेश घूम रहे हैं और वहां से क्या सीखकर आये और उसे कब तक इम्प्लीमेंट करवाएंगे खुदा ही जाने।

- मुख्य सचिव जैन के सेवाकाल को पूरे हुए 36 साल
- भाप्रसे.1989 बैच के आईएएस है अमिताभ जैन
- बतौर सीएस अमिताभ जैन का सबसे लंबा कार्यकाल
- सीएस. के नियमित पद से जुलाई में रिटायर हो चुके हैं
- शासन से उन्हें 3 माह यानि की सितंबर तक सेवावृद्धि
- संविदा में विदेश यात्रा से लौटने के बाद ख़त्म होगी संविदा

शहर सत्ता/रायपुर। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1989 बैच के अधिकारी रहे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन के शासकीय सेवा में 36 साल पूरे हो गए हैं। श्री जैन ने 21 अगस्त 1989 से शासकीय सेवा में कदम रखा था। इसके बाद से अब तक उनका सेवाकाल 36 साल का पूरा हो गया है। खास बात ये है कि श्री जैन छत्तीसगढ़ के ही मूल निवासी हैं। वे अविभाजित दुर्ग जिले के निवासी रहे हैं।

आईएएस बनने के बाद प्राथमिक रूप से शासकीय सेवा में आने के बाद वे रायपुर जिले के कलेक्टर भी रहे हैं। राज्य शासन में वे विभिन्न पदों पर रहते हुए नौकरशाही के प्रमुख पद राज्य के मुख्य सचिव बने। श्री जैन मुख्य सचिव के नियमित पद से जुलाई में रिटायर हो चुके हैं। शासन ने उन्हें 3 माह की सेवावृद्धि दी है। वर्तमान में वे मुख्य सचिव के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।

राज्य की नौकरशाही में उन्हें सरल व्यक्तित्व वाले कर्मठ और ईमानदार अधिकारी के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मुख्य सचिव बनाए गए थे। 2023 में भाजपा सरकार आने के बाद भी वे अपने पद पर सभी दायित्वों का निर्वहन करते रहे। यही नहीं, वे राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव के रूप में सेवाएं देने वाले पहले अधिकारी भी हैं।

ढांड और सिंह ने भी पूरे किए 36 साल

प्रदेश में आईएएस की सर्वाधिक सर्विस का रिकार्ड विवेक डांड और अजय सिंह के नाम है। 1981 बैच के अफसर श्री ढांड ने 2018 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। उन्होंने 36 साल 6 महीने तक प्रशासनिक सेवाएं दीं उनके बाद अजय सिंह मुख्य सचिव बनाए गए। उन्होंने 1983 में ज्वाइनिंग दी थी तथा वे 36 साल पांच महीने तक प्रशासनिक पदों पर रहे।

मुख्य सचिव रहते हुए पौने पांच साल

सेवानिवृत अफसर विवेक दांड एवं अजय सिंह सर्विस के मामले में भले ही आगे रहे हो मगर बार मुख्य सचिव अमिताभ जैन का कार्यकाल ही सबसे अधिक जहा और उनने रिकार्ड बना दिया सिर 2025 तक उनका एक्सटेंशन है मुख् हैं। केंद्र सरकार में अगर उनक कार्यकाल बड़ा दिया तो का कार्यकाल भी पूरा कर सकते हैं।

किस्मत के भी खूब धनी हैं अमिताभ

देखा जाये तो भारतमाला घोटाला, गोठां घोटाला, महादेव सट्टा एप, चांवल घोटाला, शराब घोटाला, आबकारी अधिकारीयों आदि हजारों करोड़ के इन घोटालों की समयावधी देखा जाये तो सीएस अमिताभ जैन के वक्त की ही है। हालांकि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है कि सत्ता बदलने के बाद भी उनकी जवाबदेही तय करने वाले उन्हें पूर्ण विश्वास के साथ एक अदद सवाल नहीं किये। उलटे वरिष्ठ आईएएस को सीएस बनाने की कवायद करने के बदले उन्हें सेवानिवृत भी कर दिए और एक्सटेंशन भी दे दिए!

सुलगते सवाल

- स्कूल शिक्षा जैसा विभाग 80 परसेंट से अधिक क्यों प्रभार में चल रहा है ?
- स्वास्थ्य विभाग में क्यों 90 परसेंट डीन, एमएस, सीएमओ प्रभार में हैं ?
- नौकरशाहों की फौज है मगर काम के लोगों की तादात कम क्यों ?
- पहले एक सिस्टम था, एसडीएम, एडिशनल कलेक्टर, सीईओ, फिर कलेक्टर अब ?
- भारत सरकार के आदेश के बाद भी अब तक नहीं बना एक भी डिटेंशन सेंटर
- क्या चीफ सिकरेट्री अमिताभ जैन को एक एक्सटेंशन और मिल सकता है ?

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.), मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)।